अर्थव्यवस्था की स्थिति*

ग्लोबल अनिश्चितता अपने बहुत ऊंचे स्तर से और नीचे आ गई। बाजार मूल्यांकन के बढ़ने की चिंताओं के कारण बड़े इक्विटी बाज़ारों में उतार-चढ़ाव देखा गया। 2025-26 की दूसरी तिमाही में मज़बूत घरेलू मांग से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था, पिछली छह तिमाहियों में अपनी सबसे तेज़ रफ़्तार से बढ़ी। नवंबर के उच्च-आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि मांग की स्थिति मज़बूत रहने के साथ कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधि अच्छी बनी हुई है। हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन निचले सहनशीलता स्तर से नीचे बनी रही। वित्तीय स्थितियाँ सौम्य रही, और वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह मज़बूत रहा। भारत का चालू खाता घाटा 2025-26 की दूसरी तिमाही में पिछले साल इसी समय के मुकाबले कम हुआ, जिसे कम पण्य व्यापार घाटे, मजबूत सेवा आयात और मजबूत विप्रेषण प्राप्तियों से समर्थन प्राप्त हुआ।

परिचय

नवंबर में, व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं सहित वैश्विक अनिश्चितता अपने बहुत ऊंचे स्तर से और कम हो गई। नवंबर में वैश्विक आर्थिक गतिविधि लगातार बढ़ी, जिसे नए आयात ऑर्डर और विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में व्यापार के मज़बूत होने से मदद मिली। नवंबर महीने में चीन का व्यापार अधिशेष भी इस साल में अब तक यूएसडी 1 ट्रिलियन से ज़्यादा के रिकॉर्ड पर पहुंच गया।

बाजार मूल्यांकन बढ़ने की चिंताओं के चलते बड़े इक्विटी बाज़ारों में, खासकर नवंबर के बीच में, उतार-चढ़ाव देखा गया। इक्विटी बाजार से बहिर्वाह के कारण लगातार छह महीने तक सकारात्मक अंतर्वाह के बाद, उभरते बाजार में पोर्टफोलियो प्रवाह पहली बार नकारात्मक हो गया। यूएस ट्रेजरी प्रतिफल में दोनों तरफ से उतार-चढ़ाव दिखा, जो 2026 के लिए फेड रेट आउटलुक को लेकर अनिश्चितता और दिसंबर में बैंक ऑफ जापान द्वारा दर बढ़ाने के रुख की मजबूती को दर्शाता है।

कीमती धातुओं को छोड़कर वैश्विक पण्य की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं। सेवा-क्षेत्र की मुद्रास्फीति में निरंतरता के चलते विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एई) में मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रही। इसके विपरीत, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुरूप बनी रही।

नवंबर माह के दौरान प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई मौद्रिक नीति यथास्थिति बनाए रखने की ओर झुकी रही। दिसंबर माह में कुछ प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति में स्पष्ट भिन्नता देखने को मिली। संकेत मिल रहे हैं कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती के अपने चक्र के अंत के करीब हैं और आगे चलकर आंकड़ों पर अधिक निर्भरता पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2025-26 की दूसरी तिमाही में अनुमान से अधिक, छह तिमाहियों में सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर्ज की और वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बावजूद उल्लेखनीय मजबूती का प्रदर्शन किया। घरेलू कारकों, विशेष रूप से निजी उपभोग मांग, ने विकास की गति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। नवंबर के उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि समग्र आर्थिक गतिविधि अच्छी बनी रही। मांग की स्थिति मजबूत बनी रही, और शहरी मांग के संकेतक और भी मजबूत हुए। जहां सेवा क्षेत्र की गतिविधि में लगातार मजबूत विस्तार दर्ज किया गया, वहीं विनिर्माण क्षेत्र में मंदी के कुछ संकेत मिले।

नवंबर में, माल निर्यात में वृद्धि और माल आयात में कमी के कारण पण्य व्यापार घाटा कम हुआ। अक्तूबर में निवल सेवा

* यह लेख रेखा मिश्र, आशीष थॉमस जॉर्ज, शशि कांत, विश्वजीत मोहंती, श्रेया कंसल, दुर्गा जी, अमीन अशरफ, विकास आनंद, संजना सेजवाल, भाग्यश्री चट्टोपाध्याय, आयुषी खंडेलवाल, एट्रेम अभिन्नु यादव, साक्षी चौहान, रागिनी, सिद्धार्थ आर्य, सार्थक गुलाटी, शिवम, निलावा दास, दिब्यारका चौले, मनु स्वर्णकार, नव्या सिंह, पुलस्त्य बंधोपाध्याय, अवनीश कुमार, कार्तिकेय भार्गव, समृद्धि, अथिरा सी ए, पल्लक गोयल, और खुशी सिन्हा द्वारा तैयार किया गया है। उप गवर्नर डॉ. पूनम गुप्ता द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और टिप्पणियों को कृतज्ञतापूर्वक अभिस्वीकृत किया जाता है। मोनिका सेठी और श्रोमोना गांगुली की सहकर्मी समीक्षा को भी अभिस्वीकृत किया जाता है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

निर्यात की वृद्धि धीमी रही, और सेवा निर्यात एवं आयात दोनों की वृद्धि दर में कमी आई।

नवंबर में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन लगातार तीसरे महीने यह न्यूनतम सहनशीलता स्तर से नीचे बनी रही। खाद्य अपस्फीति में नरमी और प्रतिकूल आधार प्रभाव के बने रहने के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। मूल मुद्रास्फीति (अर्थात खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) स्थिर रही; हालांकि, सोने और चांदी की कीमतों के प्रभाव को हटाने के बाद, यह अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने दिसंबर 2025 की अपनी द्विमासिक समीक्षा में सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 25 बीपीएस घटाकर 5.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एमपीसी ने अपना तटस्थ रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया। ये निर्णय हेडलाइन और मूल दोनों के लिए अनुकूल मुद्रास्फीति दृष्टिकोण से निर्देशित थे, जिसने मौद्रिक नीति को विकास की गति को और अधिक समर्थन देने के लिए गुंजाइश प्रदान की।

नवंबर के उत्तरार्ध और दिसंबर के प्रारंभ में वित्तीय परिस्थितियाँ अनुकूल बनी रहीं और प्रणाली चलनिधि अधिशेष में रही। भारित औसत मांग दर – मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य – नीतिगत रेपो दर के लगभग समरूप रहा। नवंबर में बैंक जमाओं में वृद्धि दर्ज की गई। गैर-बैंक मध्यस्थता की मजबूती के कारण वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह मजबूत बना रहा।

नवंबर के पहले पखवाड़े में भारतीय इक्विटी बाजारों में तेजी देखी गई और उसके बाद इनमें दोनों दिशाओं में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि, 2025-26 की दूसरी तिमाही के अच्छे कॉरपोरेट परिणामों और रिज़र्व बैंक तथा यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती से बाजार की भावनाएं बेहतर हुईं, लेकिन विदेशी पोर्टफोलियो में कमी और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता ने बाजार पर दबाव बनाए रखा। इक्विटी बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो बहिर्वाह से रुपये पर दबाव पड़ा; फिर भी, नवंबर में रुपये की अस्थिरता पिछले महीने की तुलना में कम रही और अधिकांश प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम बनी रही।

चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत के बाह्य क्षेत्र ने मज़बूती का प्रदर्शन किया। 2025-26 की दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम हुआ, जिसका मुख्य कारण पण्य व्यापार घाटे में कमी, सेवाओं के व्यापार में मजबूत अधिशेष और स्थिर विप्रेषण था। हालांकि, वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण पूंजी प्रवाह सीमित रहा। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ भारत की बाह्य वित्तपोषण आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करने के लिए पर्याप्त रहीं।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, इस आलेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे बदलावों को शामिल करता है। खंड III घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन प्रस्तुत करता है। खंड IV भारत की वित्तीय स्थितियों का सार प्रस्तुत करता है और खंड V निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

II. वैश्विक परिदृश्य

नवंबर में वैश्विक अनिश्चितता में कमी जारी रही, जिससे अक्तूबर में देखी गई मामूली गिरावट और बढ़ गई, हालांकि अनिश्चितता सूचकांकों का स्तर ऊंचा बना रहा। अमेरिकी व्यापार वार्ताओं में नई गति आने और अमेरिकी सरकार के कामकाज ठप होने के बाद स्थिति में सुधार होने से विश्व व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं में कमी आई। वित्तीय बाजार में अस्थिरता, जो नवंबर के तीसरे सप्ताह में एआई के अत्यधिक मूल्यांकन को लेकर चिंताओं के कारण बढ़ गई थी, बाद में मजबूत कॉरपोरेट आय के कारण कम हो गई। हालांकि, दिसंबर के मध्य में एआई निवेशों को लेकर नए सिरे से संदेह पैदा होने के साथ अस्थिरता फिर से उभर आई (चार्ट II.1ए और II.1बी)।

नवंबर के वैश्विक संयुक्त पीएमआई ने आर्थिक गतिविधि में विस्तार का संकेत देना जारी रखा, हालांकि पिछले महीने की तुलना में इसकी गति धीमी रही। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव कम होने के बाद चीन से निर्मित वस्तुओं और

चार्ट II.1: वैश्विक अनिश्चितता में और नरमी आई, बाजारों में उतार-चढ़ाव अस्थिर रहा

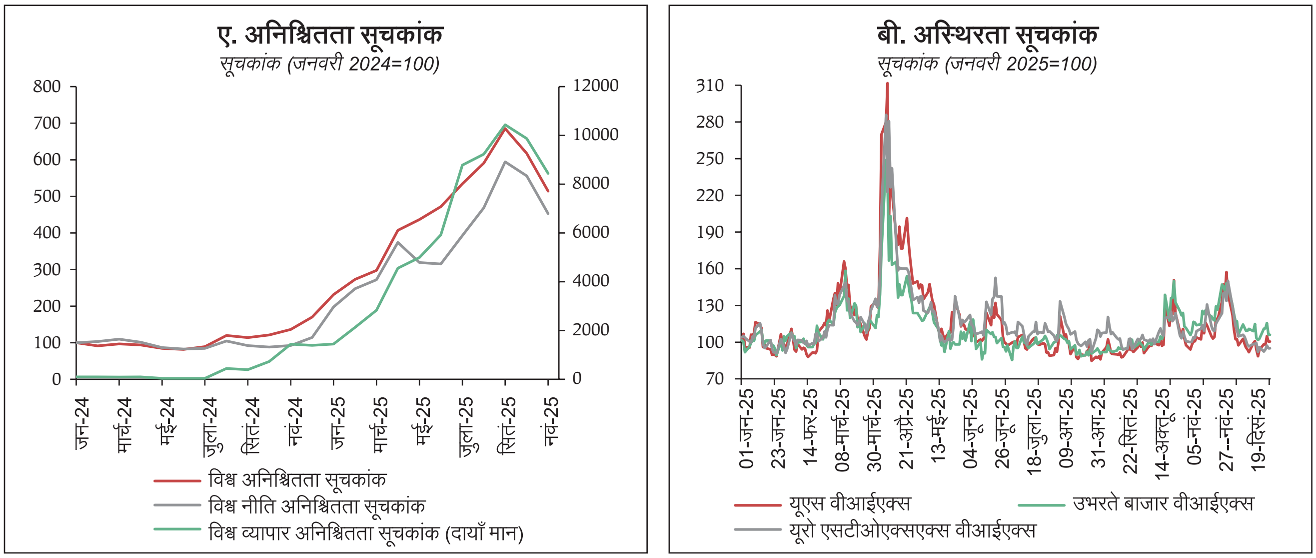

स्रोत: विश्व अनिश्चितता सूचकांक (डबल्यूयूआई) डेटाबेस; और ब्लूमबर्ग

सेवाओं के बेहतर व्यापार से नए निर्यात ऑर्डर को समर्थन मिला, जो लगातार सात महीनों तक संकुचन के बाद स्थिर हो गए (सारणी II.1)।

पीएमआई सूचकांकों से पता चलता है कि कनाडा को छोड़कर प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (एई) में व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार हुआ। प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में, भारत और चीन में व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार हुआ, जबकि ब्राजील में इसमें गिरावट आई। नए निर्यात ऑर्डर के संदर्भ में, भारत और चीन के नेतृत्व वाली ईएमडीई में एक बार फिर वृद्धि देखी गई, जबकि अधिकांश एई में निरंतर गिरावट जारी रही (चार्ट II.2ए और II.2बी)।

वैश्विक पण्य की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं। पण्य बाजारों में भी विभिन्न उतार-चढ़ाव देखने को मिले, जिसमें सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का रुझान रहा। नवंबर के लिए वर्ल्ड बैंक कमोडिटी प्राइस इंडेक्स स्थिर रहा क्योंकि ऊर्जा की कीमतों में गिरावट

सारणी II.I: वैश्विक पीएमआई संयुक्त में हल्की नरमी आई, निर्यात ऑर्डर संकुचन से बाहर आए

	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्तू-25	नवं-25
पीएमआई संयुक्त	52.4	52.6	51.8	51.5	52.1	50.8	51.2	51.7	52.5	52.9	52.5	52.9	52.7
पीएमआई विनिर्माण	50.1	49.6	50.1	50.6	50.3	49.8	49.5	50.4	49.7	50.9	50.7	50.8	50.5
पीएमआई सेवाएँ	53.1	53.8	52.2	51.5	52.7	50.8	52	51.8	53.5	53.3	52.9	53.4	53.3
पीएमआई एक्सपोर्ट ऑर्डर	49.3	48.7	49.6	49.7	50.1	47.5	48.0	49.1	48.5	48.9	49.7	48.5	50.0
पीएमआई एक्सपोर्ट ऑर्डर: विनिर्माण	48.6	48.2	49.4	49.6	50.1	47.3	48.0	49.2	48.2	48.7	49.5	48.3	49.9
पीएमआई एक्सपोर्ट ऑर्डर: सेवाएँ	51.3	50.3	50.2	50.2	50.1	48.2	47.9	48.7	49.4	49.3	50.1	49.3	50.3

50

<<<<<<संकुचन--विस्तार>>>>>>

टिप्पणियाँ: 1. क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई), एक प्रसार सूचकांक, पिछले महीने की तुलना में प्रत्येक चर में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, और यह दर्शाता है कि क्या प्रत्येक चर में बढ़ोतरी/सुधार हुआ है, गिरावट/कमी आई है या वह अपरिवर्तित रहा है। पीएमआई मान > 50 होने पर विस्तार, 50> होने पर संकुचन और =50 होने पर 'कोई परिवर्तन नहीं' का संकेत मिलता है।

2. हीट मैप अप्रैल 2023 से मई 2025 तक के डेटा पर लागू है। मैप को विभिन्न रंगों में दर्शाया गया है - लाल सबसे निम्न मान को दर्शाता है, पीला 50 (या अपरिवर्तित मान) को दर्शाता है, और हरा प्रत्येक पीएमआई शृंखला में उच्चतम मान को दर्शाता है।

स्रोत: एस&पी ग्लोबल।

चार्ट II.2: क्रय प्रबंधकों का सूचकांक: विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में तुलना

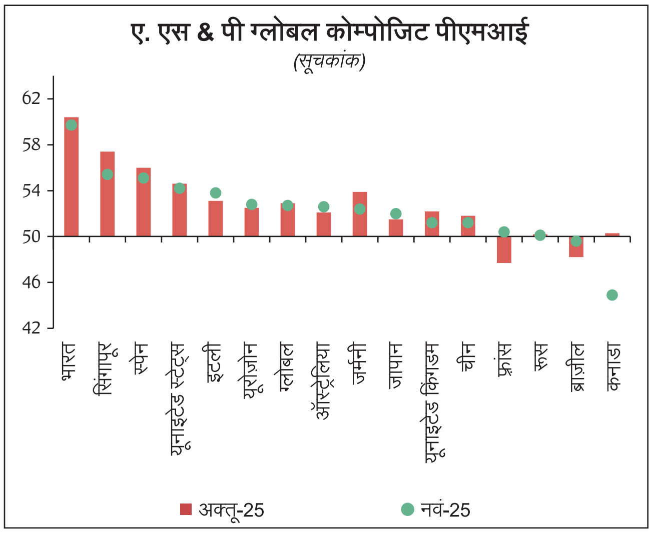

टिप्पणी: पीएमआई मान में 50 का स्तर गतिविधि में 'कोई परिवर्तन नहीं', > 50 होने पर विस्तार, 50 > होने पर संकुचन का संकेत मिलता है।
स्रोत: एस&पी ग्लोबल

की भरपाई गैर-ऊर्जा वस्तुओं की कीमतों में मामूली वृद्धि से हो गई। खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक लगातार तीसरे महीने गिरा, जिसका मुख्य कारण डेयरी उत्पाद, मांस, चीनी और वनस्पति तेल थे (चार्ट II.3ए)। ब्लूमबर्ग कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में कीमती धातुओं के कारण और वृद्धि हुई। फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के चलते नवंबर में सोने की कीमतों में वृद्धि हुई और दिसंबर में भी यह वृद्धि जारी रही। आपूर्ति में व्यवधान और टैरिफ जोखिमों के कारण कीमतों में विकृति के चलते तांबे की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट का रुझान रहा, जिसका कारण अधिक आपूर्ति की आशंका और रूस-यूक्रेन शांति समझौते की संभावना को लेकर बढ़ती आशावादिता थी (चार्ट II.3बी)।

विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति ने विरोधाभासी परिदृश्य प्रस्तुत किए। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं

चार्ट II.3: पण्य वस्तु और खाद्य कीमतें

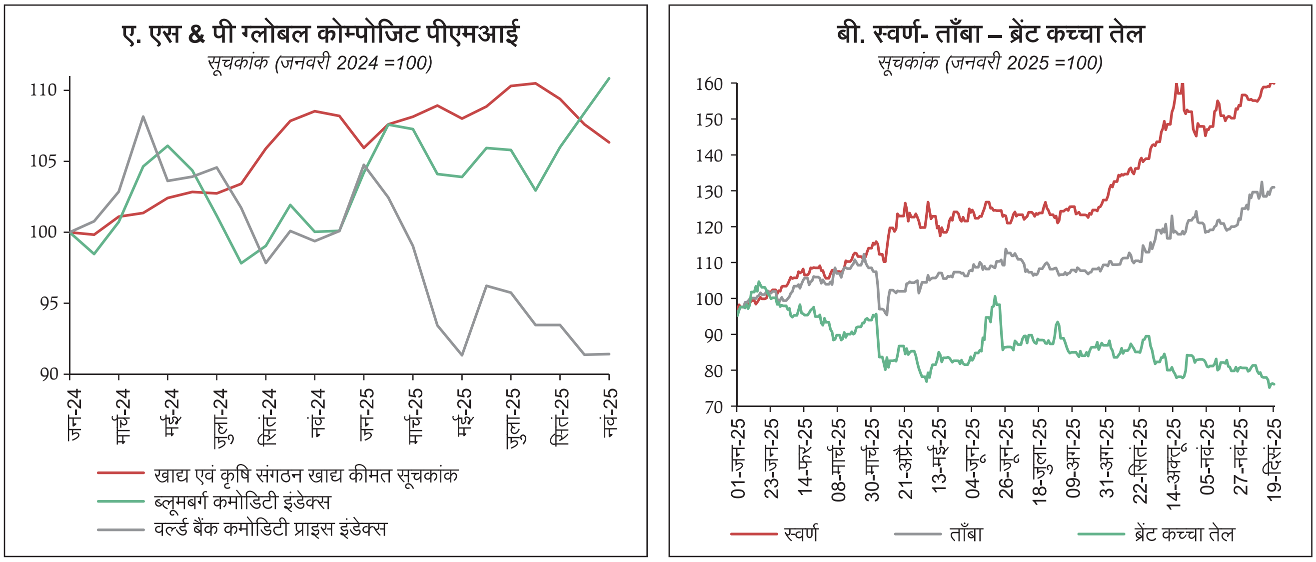

स्रोत: खाद्य एवं कृषि संगठन; ब्लूमबर्ग; और वर्ल्ड बैंक।

चार्ट II.4: हेडलाइन मुद्रास्फीति

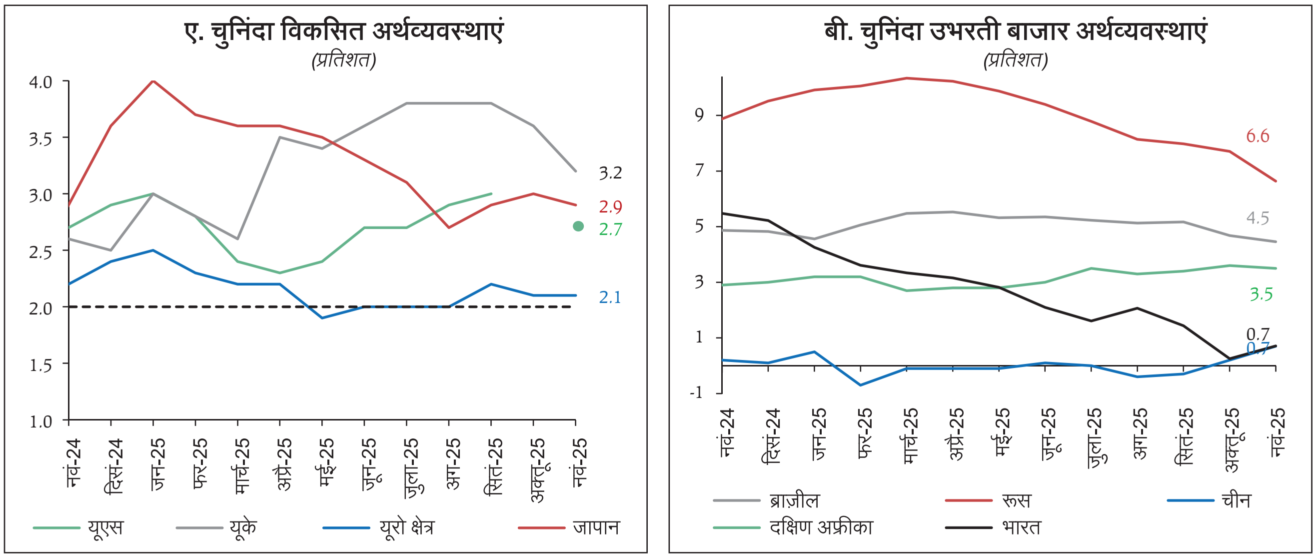

स्रोत:ब्लूमबर्ग।

(एई) में मुद्रास्फीति में कुछ कमी आई, लेकिन सेवाओं की बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच यह उच्च स्तर पर बनी रही। यूरो क्षेत्र में, सेवाओं की लागत में वृद्धि के कारण नवंबर में हेडलाइन मुद्रास्फीति में और वृद्धि हुई, जबकि अमेरिका में मुद्रास्फीति में कमी आई। यूके में खाद्य और पेय के कारण मुद्रास्फीति छह महीने के निचले स्तर पर आ गई। जापान में भी खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट आई (चार्ट II.4ए)। प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में, चीन में खाद्य कीमतों में उछाल के कारण मुद्रास्फीति 21 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जबकि मूल मुद्रास्फीति स्थिर रही। इसके विपरीत, ब्राजील और रूस में खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण मुद्रास्फीति का दबाव कम हुआ, जहां हेडलाइन मुद्रास्फीति सितंबर 2023 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई। दक्षिण अफ्रीका में परिवहन लागत में कमी के कारण मुद्रास्फीति में कमी आई (चार्ट II.4बी)।

तकनीकी कंपनियों के अत्यधिक मूल्यांकन को लेकर चिंताओं के चलते अमेरिका के इक्विटी बाजार नवंबर के तीसरे सप्ताह तक गिरे रहे। बाद में, मजबूत कॉरपोरेट परिणामों के कारण बाजारों में सुधार हुआ और फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद दिसंबर में इनमें मामूली उछाल आया। हालांकि, मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के फिर से उभरने से इनमें गिरावट आई। वित्तीय और आईटी क्षेत्रों की मजबूत आय के चलते यूरोपीय शेयर में नवंबर-दिसंबर के दौरान तेजी आई, लेकिन तकनीकी कंपनियों के मूल्यांकन को लेकर आशंकाएं फिर से बढ़ने के कारण इनमें गिरावट दर्ज की गई। राजकोषीय प्रोत्साहन के चलते जापान के शेयर बाजार में नवंबर के अंत से निवल लाभ देखा गया, लेकिन मौद्रिक सख्ती की बढ़ती आशंकाओं के चलते इसमें फिर से गिरावट आई। तकनीकी शेयरों में गिरावट के चलते चीनी शेयर बाजार में मामूली गिरावट आई, हालांकि उम्मीद से बेहतर निर्यात और उच्च प्रदर्शन करने वाली प्रतिभूति कंपनियों के लिए विनियामकीय ढील ने इसे समर्थन दिया (चार्ट II.5ए)।

नवंबर में, ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में गिरावट आई। इसके बाद, बैंक ऑफ जापान की कठोर टिप्पणियों के बाद दिसंबर की शुरुआत में प्रतिफल बढ़कर 16 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि दिसंबर में फेड की नीति के बाद प्रतिफल में कुछ नरमी आई, लेकिन 2026 के लिए फेड दर परिदृश्य पर अनिश्चितता के कारण गिरावट सीमित रही। जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉण्ड यील्ड स्प्रेड, औसतन, नवंबर-दिसंबर में अब तक क्रमिक रूप से कम हुआ है (चार्ट II.5बी)। नवंबर में स्थिर रहने के बाद, दिसंबर में कमजोर आर्थिक आंकड़ों और फेड द्वारा नीतिगत दर में कटौती के कारण अन्य अर्थव्यवस्थाओं

चार्ट II.5: वैश्विक वित्तीय बाजार

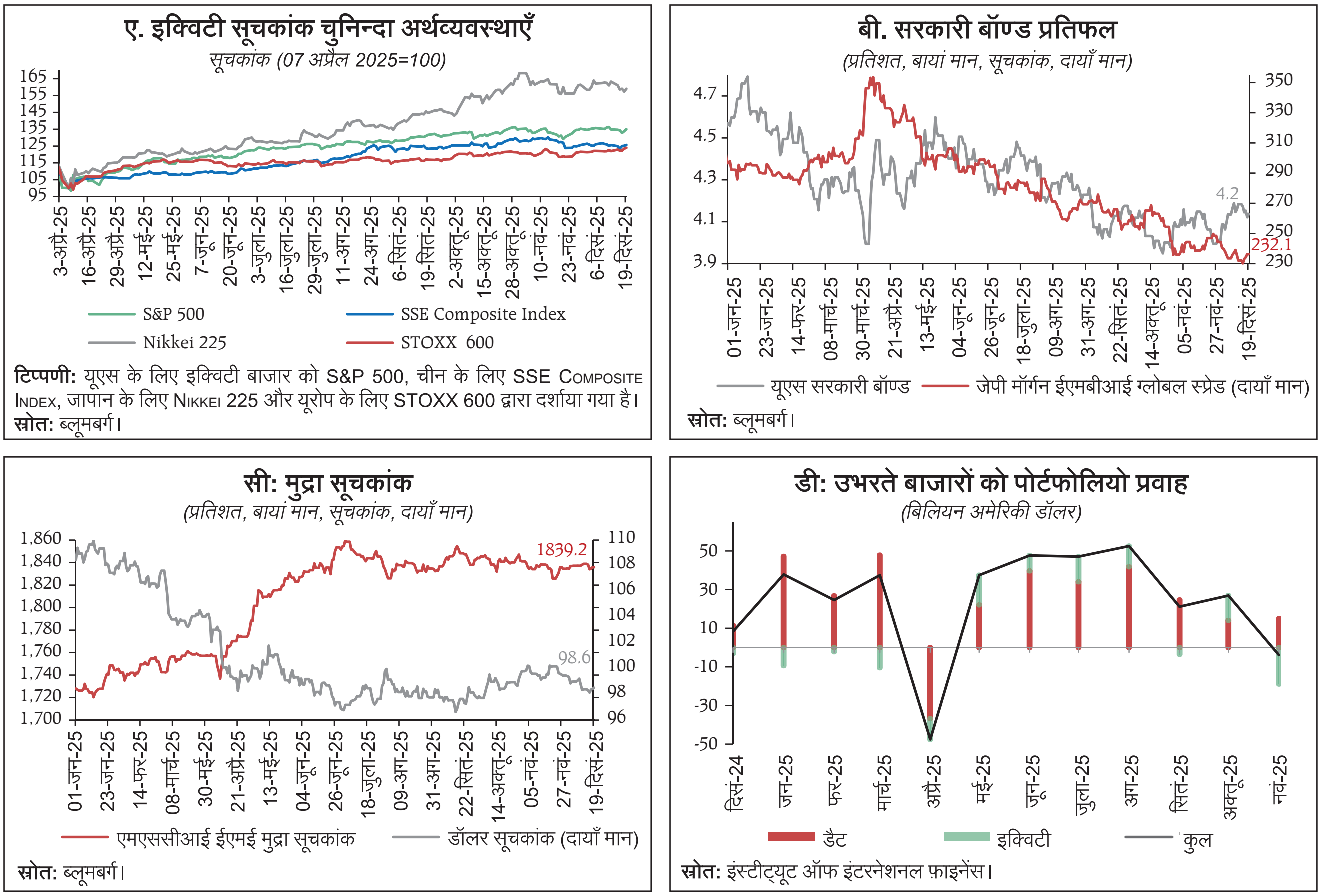

पर प्रतिफल लाभ के सिकुड़ने की चिंताओं के चलते अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ (चार्ट II.5सी)। छह महीने तक लगातार अंतर्वाह के बाद नवंबर में उभरते बाज़ारों में पोर्टफोलियो प्रवाह नकारात्मक हो गया। कमजोर वैश्विक जोखिम लेने की प्रवृत्ति के कारण इक्विटी बाजारों में महत्वपूर्ण बहिर्वाह दर्ज किया गया, जबकि ऋण प्रवाह स्थिर और सकारात्मक बना रहा (चार्ट II.5डी)।

नवंबर 2025 में, अधिकांश प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में, दक्षिण कोरिया ने वित्तीय स्थिरता जोखिमों पर यथास्थिति बनाए रखी, न्यूजीलैंड ने विकास संबंधी चिंताओं के कारण दर को तीन साल से अधिक के निचले स्तर पर कम कर दिया। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के मामले में, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया ने नवंबर में अपनी ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने विकास संबंधी चिंताओं के कारण नीतिगत दर में कमी की।

दिसंबर महीने में कुछ प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति में स्पष्ट भिन्नता देखने को मिली। जहां यूएस और यूके ने श्रम बाजार की कमजोर स्थिति को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती की, वहीं जापान ने मुद्रास्फीति के लक्ष्य से ऊपर रहने के कारण अपनी नीतिगत दर को 30 वर्षों के उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया। दिसंबर में बैठक करने वाले 15 केंद्रीय बैंकों में से सात ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, यूरो क्षेत्र और स्वीडन ने अपनी प्रमुख दरों को अपरिवर्तित रखा। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इंडोनेशिया और ब्राजील ने क्रमशः लगातार तीसरी और चौथी बैठक में अपनी ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। रूस, फिलीपींस, थाईलैंड और मैक्सिको ने अपनी नीतिगत दरों में कटौती की (चार्ट II.6)।

चार्ट II.6: केंद्रीय बैंकों ने दिसंबर में विविध नीतिगत दरों के रास्ते अपनाएं

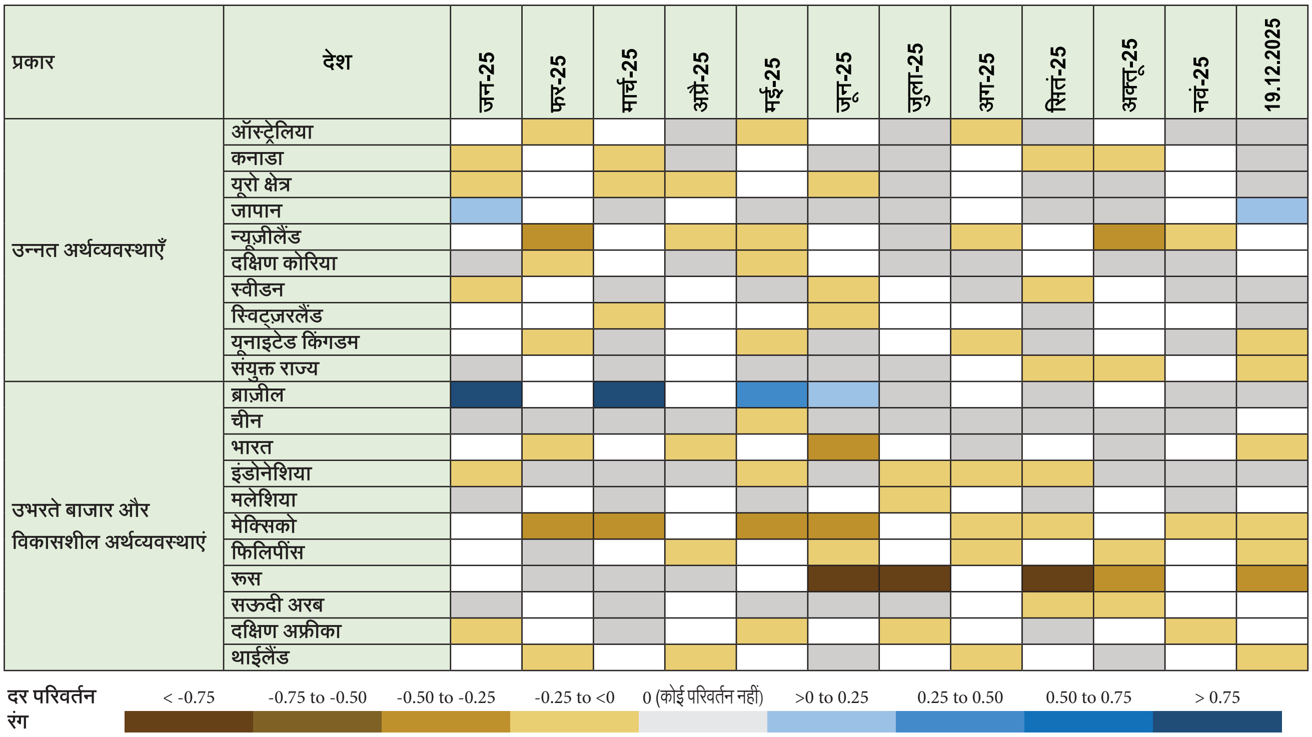

टिप्पणी: सफ़ेद रंग में दर्शाए गए ब्लॉक ऑफ-पॉलिसी माह की ओर संकेत करते हैं।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

III. घरेलू घटनाक्रम

मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2025-26 की दूसरी तिमाही में पिछले छह तिमाहियों में सबसे तेज गति से विकास किया। आपूर्ति पक्ष पर, वैश्विक व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं के बावजूद सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों ने मजबूत वृद्धि प्रदर्शित की। उपलब्ध उच्च-आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि नवंबर में त्योहारों के बाद समग्र आर्थिक गतिविधि स्थिर रही। जहां सेवा क्षेत्र में मजबूत विस्तार जारी रहा, वहीं विनिर्माण क्षेत्र में मंदी के कुछ संकेत दिखे।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने दिसंबर 2025 की अपनी द्विमासिक समीक्षा में सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 25 बीपीएस घटाकर 5.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एमपीसी ने तटस्थ रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया। ये निर्णय हेडलाइन और मूल दोनों के लिए अनुकूल मुद्रास्फीति दृष्टिकोण से निर्देशित थे, जिसने मौद्रिक नीति को विकास की गति को और अधिक समर्थन देने के लिए गुंजाइश प्रदान की।

कुल मांग

2025-26 की दूसरी तिमाही में, मजबूत निजी उपभोग और स्थिर निवेश के चलते वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2023-24 की चौथी तिमाही के बाद से उच्चतम स्तर है। ग्रामीण मांग में मजबूती और मुद्रास्फीति के दबाव में कमी के कारण निजी उपभोग में वृद्धि जारी रही। निवल निर्यात वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालता रहा (चार्ट III.1 और अनुलग्नक सारणी ए1)।

दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि में तीव्र उछाल के बावजूद, सांकेतिक जीडीपी में चार तिमाहियों में सबसे कम 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सांकेतिक और वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बीच अंतर का कम होना जीडीपी अपस्फीतिकारक में कमी को दर्शाता है, जो घटकर 0.5 प्रतिशत के निचले स्तर पर है (चार्ट III.2)।

उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि नवंबर में त्योहारों के बाद समग्र आर्थिक गतिविधि स्थिर रही। हालांकि जीएसटी

चार्ट III.1: जीडीपी वृद्धि में भारित योगदान

(प्रतिशत अंक)

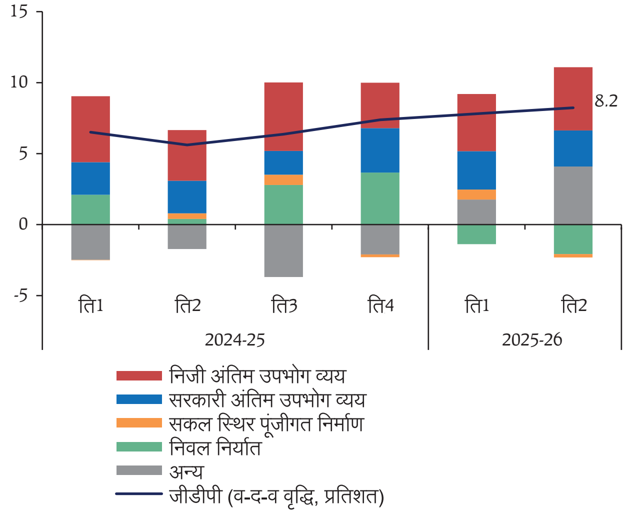

टिप्पणी: अन्य में स्टॉक में परिवर्तन, कीमती वस्तुएं और सांख्यिकीय विसंगतियाँ शामिल हैं।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)।

चार्ट III.2: जीडीपी अपस्फीतिकारक मुद्रास्फीति में कमी

(प्रतिशत)

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

राजस्व संग्रह में कमी जीएसटी दरों के युक्तिकरण से काफी हद तक प्रभावित थी, लेकिन आर्थिक गतिविधि के अन्य उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे ई-वे बिल, पेट्रोलियम खपत और डिजिटल भुगतान में वृद्धि दर्ज की गई। ई-वे बिलों के निर्माण में तीव्र वृद्धि जीएसटी सुधारों द्वारा समर्थित माल ढुलाई और माल परिवहन गतिविधि में वृद्धि का संकेत देती है। पेट्रोलियम खपत में वृद्धि निर्माण और कृषि कार्यों में तेजी के कारण हुई। डिजिटल भुगतानों ने लेनदेन मूल्य और मात्रा दोनों में मजबूत वृद्धि दर्ज की। शीत ऋतु के जल्दी शुरू होने के कारण बिजली की मांग लगातार दूसरे महीने कम हुई (सारणी III.1)।

सारणी III.1: उच्च आवृत्ति संकेतक- समग्र आर्थिक गतिविधि

संकेतक	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्तू-25	नवं-25
जीएसटी ई-वे बिल्स	16.3	17.6	23.1	14.7	20.2	23.4	18.9	19.3	25.8	22.4	21.0	8.2	27.6
जीएसटी राजस्व	0.6	7.3	12.3	9.1	9.9	12.6	16.4	6.2	7.5	6.5	9.1	4.6	0.7
टोल संग्रह	11.9	9.8	14.8	18.7	11.9	16.6	16.4	15.5	14.8	12.7	4.5	4.6	2.9
विद्युत माँग	3.7	5.1	1.3	2.4	5.7	2.8	-4.8	-2.3	2.6	3.8	3.5	-5.8	-0.6
पैट्रोलियम उपभोग	10.6	2.0	3.0	-5.2	-3.1	0.2	1.1	0.5	-4.4	4.8	7.6	-0.4	3.0
जिसमें से पेट्रोल	9.6	11.1	6.7	5.0	5.7	5.0	9.2	6.8	5.9	5.5	8.0	7.4	2.6
डीज़ल	8.5	5.9	4.2	-1.3	0.9	4.2	2.1	1.5	2.4	1.2	6.6	-0.3	4.7
एविएशन टरबाइन फ्यूल	8.5	8.7	9.4	4.2	5.7	3.9	4.4	3.3	-2.3	-2.9	-0.8	2.1	5.4
डिजिटल भुगतान- मात्रा	30.1	33.1	33.0	26.7	30.8	30.0	29.2	28.3	30.9	31.1	28.1	21.5	27.2
डिजिटल भुगतान- मूल्य	9.5	19.6	18.6	9.5	17.3	18.4	12.6	17.4	16.6	5.3	13.4	8.8	14.9

<<संकुचन -- विस्तार>>

टिप्पणियाँ: 1. सभी संकेतकों के लिए व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
2. हीट मैप अप्रैल 2023 से नवीनतम माह (जहां तक का डेटा उपलब्ध है) तक के डेटा पर लागू है। नवंबर 2025 के लिए डिजिटल भुगतान डेटा अनंतिम है।
3. हीट मैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा श्रेणी को कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदल देता है, जहां लाल निम्नतम मानों को दर्शाता है और हरा संबंधित डेटा शृंखला के उच्चतम मानों को दर्शाता है।
4. नवंबर 2025 के लिए टोल संग्रह की वृद्धि दर की गणना दैनिक डेटा को मिलाकर की गई है।

स्रोत: वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन); आरबीआई, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए); भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई); एवं पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

सारणी III.2: उच्च आवृत्ति संकेतक- मजबूत मांग स्थितियाँ

	सूचकांक	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्तू-25	नवं-25
शहरी माँग	घरेलू हवाई यात्री यातायात	13.8	10.8	14.1	12.1	9.9	9.7	2.6	3.7	-2.5	-0.5	-2.5	3.5	6.7
	खुदरा यात्री वाहन बिक्री	-11.8	-2.0	15.5	-10.3	6.3	1.6	-3.1	2.5	-0.8	0.9	5.8	10.7	19.7
ग्रामीण माँग	खुदरा वाहन बिक्री	12.0	-12.5	6.6	-7.2	-0.7	2.9	5.4	4.8	-4.3	2.8	5.2	40.5	2.1
	खुदरा ट्रैक्टर बिक्री	29.9	25.8	5.2	-14.5	-5.7	7.6	2.8	8.7	11.0	30.1	3.6	14.2	56.5
	खुदरा दो-पहिया बिक्री	16.3	-17.6	4.2	-6.3	-1.8	2.3	7.3	4.7	-6.5	2.2	6.5	51.8	-3.1

<<संकुचन -- विस्तार>>

टिप्पणियाँ: 1. सभी संकेतकों के लिए व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
2. हीट मैप अप्रैल 2023 से नवीनतम माह (जहां तक का डेटा उपलब्ध है) तक के डेटा पर लागू है।
3. यह प्रत्येक संकेतक की डेटा श्रेणी को कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदल देता है, जहां लाल सबसे निम्न मान को दर्शाता है और हरा संबंधित डेटा शृंखला के सबसे उच्च मान को दर्शाता है।
4. नवंबर 2025 के लिए घरेलू हवाई यात्री यातायात की वृद्धि दर की गणना दैनिक डेटा को मिलाकर की गई है।

स्रोत: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया; फ़ैडरेशन ऑफ आटोमोबाइल डीलर्स असोशिएशन्स (एफएडीए); और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

नवंबर के दौरान, समग्र मांग की स्थिति मजबूत बनी रही। त्योहारी सीजन में आई तेजी के चलते शहरी मांग के संकेतक और भी मजबूत हुए। जीएसटी लाभ, विवाह सीजन की मांग और बेहतर आपूर्ति के कारण खुदरा यात्री वाहनों की बिक्री एक वर्ष से अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। घरेलू हवाई यात्री यातायात ने मई 2025 के बाद से अपनी सबसे तेज वृद्धि दर्ज की। रबी सीजन की सकारात्मक संभावनाओं, जीएसटी दरों में कमी और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण खुदरा ट्रैक्टरों की बिक्री में उल्लेखनीय तेजी आई। हालांकि, ग्रामीण मांग के अन्य उच्च आवृत्ति संकेतक, जैसे खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री, त्योहारी सीजन के बाद प्रतिकूल आधार प्रभाव (सारणी III.2) के साथ-साथ तीव्र मंदी के शिकार हुए।[1]

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (15 दिसंबर को जारी) के अनुसार, नवंबर में अखिल भारतीय बेरोजगारी दर घटकर 4.7 प्रतिशत हो गई, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गिरावट देखी गई। श्रम बल सहभागिता दर सात महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, साथ ही श्रमिक जनसंख्या अनुपात में भी सुधार हुआ। विनिर्माण क्षेत्र के लिए पीएमआई रोजगार में नवंबर में मंदी देखी गई, लेकिन क्षेत्र में विस्तार बना रहा। सेवाओं के लिए पीएमआई रोजगार स्थिर रहा। नवंबर में नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स में उछाल आया, जिसका मुख्य कारण शिक्षा, आतिथ्य और रियल एस्टेट जैसे गैर-आईटी क्षेत्रों में नई भर्तियां थीं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत काम की मांग में गिरावट जारी रही, जो ग्रामीण श्रम बाजार की स्थितियों में सुधार का संकेत देती है (सारणी III.3)।

अप्रैल-अक्तूबर 2025 के दौरान, बजट अनुमान (बीई) के प्रतिशत के रूप में केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक था, जबकि बीई के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा कम था (चार्ट III.3ए)।[2] उच्च राजकोषीय घाटे का कारण उच्च पूंजीगत व्यय और निवल कर राजस्व में कमी थी।[3] केंद्र का राजस्व व्यय स्थिर रहा, ब्याज भुगतान में उच्च वृद्धि दर्ज की गई और प्रमुख सब्सिडी में कमी आई।[4] प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह दोनों में कर राजस्व की धीमी वृद्धि देखी गई।[5]

[1] प्रतिकूल आधार प्रभाव 2024 में नवंबर में त्योहारी मौसम होने के कारण उत्पन्न हुए।

[2] लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार।

[3] अप्रैल-अक्तूबर 2025-26 के दौरान, पूंजीगत व्यय और निवल कर राजस्व में क्रमशः 32.4 प्रतिशत और -2.4 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। केंद्र के निवल कर संग्रह में संकुचन हुआ क्योंकि इस अवधि के दौरान सकल कर राजस्व में हुई वृद्धि केंद्र से राज्यों को कर हस्तांतरण में हुई वृद्धि की भरपाई से अधिक हो गई।

[4] अप्रैल-अक्तूबर 2025-26 के दौरान, ब्याज भुगतान और प्रमुख सब्सिडी पर केंद्र के खर्च में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि क्रमशः 13.0 प्रतिशत और (-) 0.8 प्रतिशत रही।

[5] प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि दर अप्रैल-अक्तूबर 2024-25 की क्रमशः 12.3 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत से घटकर अप्रैल-अक्तूबर 2025-26 में क्रमशः 6.0 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत हो गई। प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में से केवल निगम कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई।

सारणी III.3: रोजगार के लिए उच्च आवृत्ति संकेतकों में मजबूती

सूचकांक	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्तू-25	नवं-25
बेरोजगारी दर (पीएलएफएस: अखिल भारतीय)						5.1	5.6	5.6	5.2	5.1	5.2	5.2	4.7
बेरोजगारी दर (पीएलएफएस: ग्रामीण)						4.5	5.1	4.9	4.4	4.3	4.6	4.4	3.9
बेरोजगारी दर (पीएलएफएस: शहरी)						6.5	6.9	7.1	7.2	6.7	6.8	7.0	6.5
नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स	2.0	8.7	3.9	4.0	-1.5	8.9	0.3	10.5	6.8	3.4	10.1	-9.3	23.5
पीएमआई रोजगार : विनिर्माण	52.9	53.4	54.8	54.5	53.4	54.2	54.9	55.1	53.3	53.1	52.1	52.4	50.9
पीएमआई रोजगार : सेवाएँ	56.6	55.5	56.3	56.2	52.5	53.9	57.1	55.1	51.4	52.2	51.9	51.4	51.6
मनरेगा: कार्य मांग	3.9	8.2	14.4	2.8	2.2	-6.5	4.4	4.4	-12.3	-26.2	-27.1	-35.1	-31.9

<<संकुचन --- विस्तार >>

टिप्पणियाँ: 1.सभी पीएलएफएस संकेतक चालू साप्ताहिक स्थिति के अनुसार हैं और 15 वर्ष और उससे अधिक के लोगों के लिए हैं।
2. नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स और मनरेगा कार्य मांग के लिए विस्तार व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
3. हीट मैप अप्रैल 2023 से नवीनतम माह (जहां तक डेटा उपलब्ध है) के डेटा पर लागू है।
4. हीट मैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा श्रेणी को कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदल देता है, जहां लाल निम्नतम मानों को दर्शाता है और हरा संबंधित डेटा शृंखला के उच्चतम मानों को दर्शाता है।
5. सभी पीएमआई मान को सूचकांक रूप में रिपोर्ट किया जाता है। पीएमआई मान > 50 होने पर विस्तार, 50> होने पर संकुचन और =50 होने पर 'कोई परिवर्तन नहीं' का संकेत मिलता है। पीएमआई हीट मैप में लाल सबसे निम्न मान को दर्शाता है, पीला 50 (या अपरिवर्तित मान) को दर्शाता है, और हरा प्रत्येक पीएमआई शृंखला में उच्चतम मान को दर्शाता है।

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार; इंफो एज; और एस&पी ग्लोबल।

गैर-कर राजस्व और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के सशक्त प्रदर्शन ने निवल कर राजस्व में आई कमी की भरपाई कर दी, और कुल प्राप्तियों में वृद्धि को सहारा दिया।[6]

अप्रैल-अक्तूबर 2025 के दौरान वित्तीय वर्ष के बीई के अनुपात के रूप में राज्यों के घाटे के संकेतक, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम थे (चार्ट III.3बी)। इस सुधार का मुख्य कारण राजस्व व्यय में वृद्धि की गति में आई भारी कमी

चार्ट III.3: घाटा संकेतक (अप्रैल-अक्तूबर)

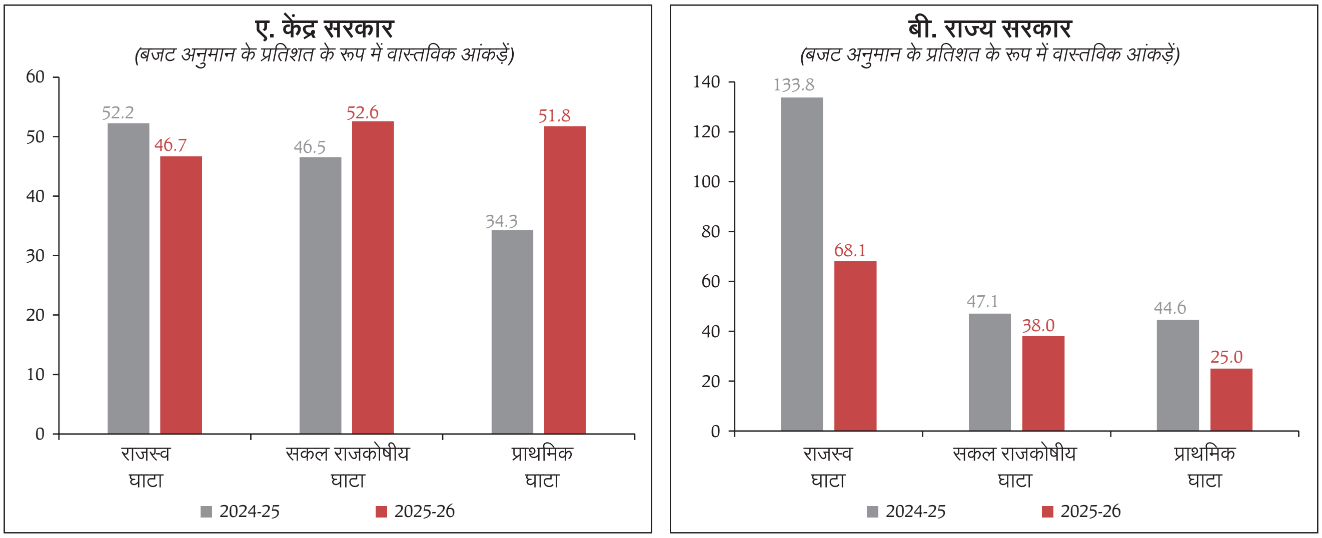

टिप्पणी: डेटा 23 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
स्रोत: महालेखा नियंत्रक; भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; और केंद्रीय बजट दस्तावेज।

[6] केंद्र की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां (जिसमें कर राजस्व के साथ-साथ गैर-कर राजस्व भी शामिल है) और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (अर्थात उधार के अलावा अन्य पूंजीगत प्राप्तियां) शामिल हैं।

थी। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत, राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि मज़बूत बनी रही, जबकि एसजीएसटी में वृद्धि की गति धीमी हो गई।

इस वर्ष अब तक (अप्रैल-नवंबर) के दौरान, पण्य व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा, जिसका मुख्य कारण पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोना था।[7] इस अवधि के दौरान भारत के पण्य निर्यात और आयात में व्यापक विस्तार देखने को मिला।[8]

नवंबर में, पण्य-निर्यात में तेजी और पण्य-आयात में कमी के कारण पण्य व्यापार घाटा कम हो गया।[9] अक्तूबर की तुलना में नवंबर में आयात में जो कमी आई, उसकी मुख्य वजह सोना था, क्योंकि त्योहारों के बाद इसकी मांग कम हो गई। नतीजतन, नवंबर में पण्य व्यापार घाटे में सोने का हिस्सा 11 प्रतिशत रहा, जो अक्तूबर में 33 प्रतिशत था (चार्ट III.4)। पिछले दो महीनों में लगातार गिरावट के बाद, नवंबर के महीने में अमेरिका को होने वाला निर्यात बढ़ गया।[10]

11 दिसंबर को, मेक्सिको ने उन देशों (जिनके साथ उसका कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है) से आयात किए जाने वाले 1400 उत्पादों पर 5 से 50 प्रतिशत तक का अधिक आयात शुल्क लगा दिया। मेक्सिको, इंजीनियरिंग सामानों के तीन उप-क्षेत्रों—यानी, दो और तीन-पहिया वाहन, मोटर वाहन/कारें, और वाहनों के पुर्जे और हिस्से—के लिए भारत का एक प्रमुख निर्यात गंतव्य है।[11] 2024-25 के दौरान, इन

चार्ट III.4: भारत का पण्य व्यापार

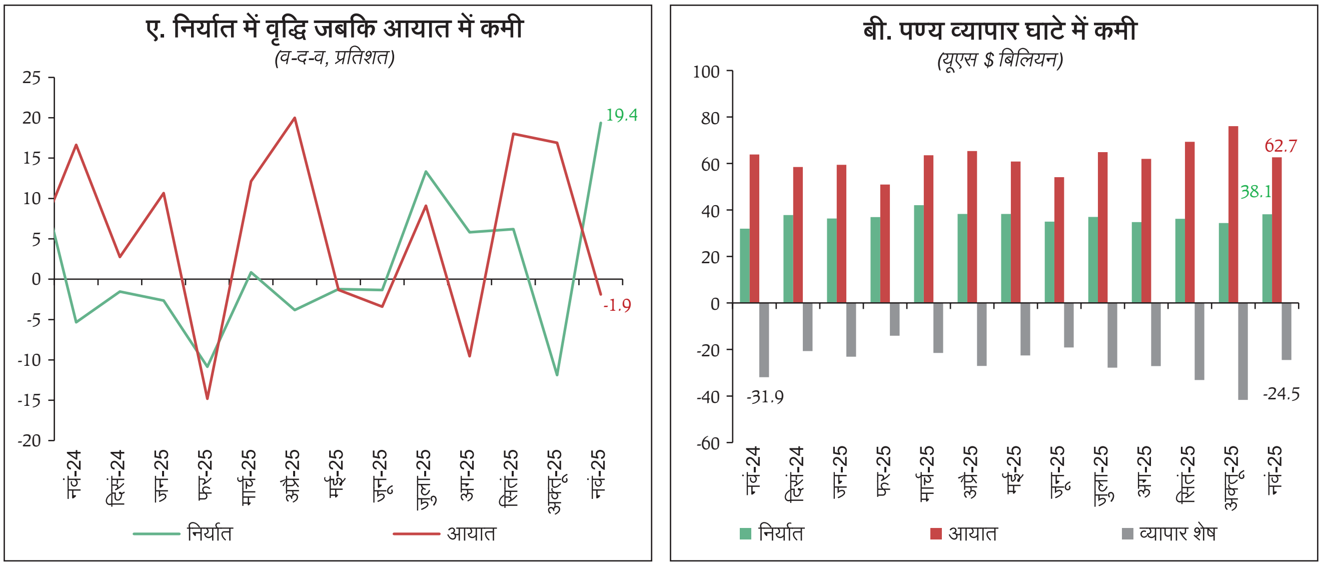

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई&एस।

---

[7] अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान पण्य व्यापार घाटा 223.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान यह 203.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

[8] 2025-26 (अप्रैल-नवंबर) में 30 प्रमुख वस्तुओं में से 17 (निर्यात-समूह का 58.2 प्रतिशत) और 30 प्रमुख वस्तुओं में से 19 (आयात समूह का 51.9 प्रतिशत) में विस्तार दर्ज किया गया।

[9] नवंबर 2025 में पण्य घाटा घटकर 24.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो नवंबर 2024 में 31.9 अरब अमेरिकी डॉलर था। नवंबर 2025 में पण्य निर्यात 38.1 अरब अमेरिकी डॉलर रहा [19.4 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)]। इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न और आभूषण; दवाइयां और फार्मास्यूटिकल्स; और पेट्रोलियम उत्पाद जैसे प्रमुख क्षेत्रों ने निर्यात को बढ़ावा दिया, जबकि चावल, प्लास्टिक और लिनोलियम, कालीन, तिलहन और जूट निर्माण (फर्श कवरिंग सहित) ने निर्यात को नीचे खींच लिया। शीर्ष 20 प्रमुख गंतव्यों में से 14 को निर्यात में वृद्धि हुई, जिसमें अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन जैसे गंतव्यों को निर्यात में वृद्धि हुई, जबकि नीदरलैंड और सिंगापुर को निर्यात में कमी आई। नवंबर 2025 में पण्य आयात 62.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा [1.9 प्रतिशत की कमी (वर्ष-दर-वर्ष)]। सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, वनस्पति तेल, कोयला, कोक और ब्रिकेट; कृत्रिम रेज़िन और प्लास्टिक सामग्री ने आयात को नीचे खींच लिया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान, उर्वरक (कच्चे और निर्मित), मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, मशीनरी (विद्युत और गैर-विद्युत) और चांदी ने महीने के दौरान आयात में सकारात्मक योगदान दिया।

[10] नवंबर 2025 में अमेरिका को पण्य निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष 22.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[11] 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में मेक्सिको का हिस्सा 1.3 प्रतिशत था। भारत ने 2024-25 में मेक्सिको को 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के इंजीनियरिंग सामान का निर्यात किया, जो मेक्सिको को कुल निर्यात का 61.5 प्रतिशत और कुल इंजीनियरिंग सामान निर्यात का 3.0 प्रतिशत था। 2024-25 में मेक्सिको को 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के दो-तीन पहिया वाहन, मोटर वाहन/कारें और ऑटो कंपोनेंट और पार्ट्स का निर्यात किया गया।

क्षेत्रों में भारत के कुल निर्यात में मेक्सिको की हिस्सेदारी 5-12 प्रतिशत रही। चूंकि भारत का मेक्सिको के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं है, इसलिए इन सामानों के भारतीय निर्यात पर लगने वाले टैरिफ 1 जनवरी 2026 से 20 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएंगे।

अक्तूबर में निवल सेवाओं के निर्यात की वृद्धि दर धीमी रही, जिसमें सेवाओं के निर्यात और आयात, दोनों की गति में सुस्ती देखी गई।[12] सॉफ्टवेयर और परिवहन सेवाओं के कमज़ोर प्रदर्शन के कारण सेवाओं के निर्यात और आयात में वृद्धि की गति धीमी पड़ गई (चार्ट III.5)।

चार्ट III.5: सेवा क्षेत्र में निर्यात में वृद्धि जारी रही, यद्यपि इसकी गति धीमी रही

(प्रतिशत, व-द-व)

स्रोत: आरबीआई।

कुल आपूर्ति

आपूर्ति पक्ष पर, वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में वृद्धि 2025-26 की पहली तिमाही के 7.6 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी तिमाही में 8.1 प्रतिशत हो गई। जीवीए वृद्धि में यह बढ़ोतरी औद्योगिक गतिविधियों में आई ज़ोरदार तेज़ी और सेवा क्षेत्र में बनी रही मज़बूती के कारण हुई (चार्ट III.6 और अनुलग्नक सारणी ए2)। विनिर्माण क्षेत्र के मज़बूत प्रदर्शन के चलते औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि में तेज़ी आई। सेवा क्षेत्र ने अपनी वृद्धि की गति को बनाए रखा, जिसमें वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएँ इसकी वृद्धि को आगे बढ़ाने वाले मुख्य उप-घटक रहे। कृषि और संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि में कुछ नरमी देखने को मिली, जिसका कारण अत्यधिक वर्षा के चलते फसलों को हुए स्थानीय नुकसान की वजह से उम्मीद से कम खरीफ उत्पादन रहा।

कृषि

2025-26 के कृषि उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमानों से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण अनाज उत्पादन—विशेष रूप से चावल और मक्का—में आई तेज़ी है। खाद्यान्न श्रेणी के अंतर्गत आने वाली अन्य सभी फसलों के उत्पादन में गिरावट आई है, जो आंशिक रूप से अत्यधिक वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान को दर्शाती है (चार्ट III.7)।[13]

खरीफ विपणन सीज़न 2025-26 के लिए अब तक, चावल की खरीद पिछले साल की तुलना में ज़्यादा रही है।[14]

चार्ट III.6: जीवीए विकास में भारित योगदान

(प्रतिशत अंक)

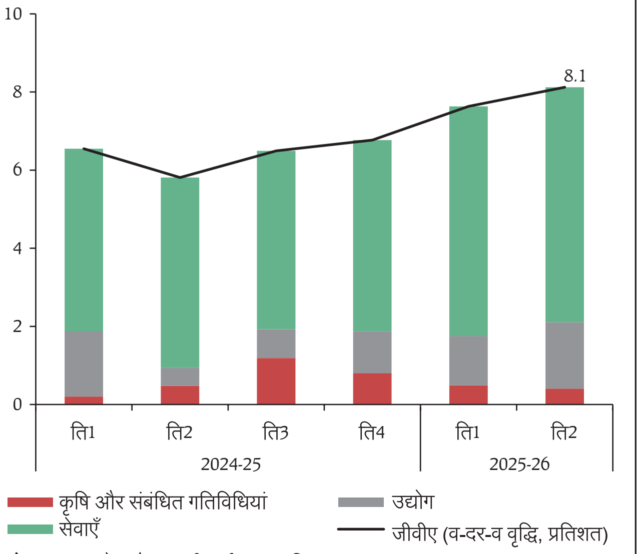

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

---

[12] अक्तूबर 2025 में निवल सेवा निर्यात में 1.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई और यह 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि अक्तूबर 2024 में यह 17.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-अक्तूबर 2025 के दौरान, निवल सेवा निर्यात बढ़कर 116.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान यह 101.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

[13] प्रथम वार्षिक पूर्वानुमान के अनुसार, 2025-26 में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 173.3 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2024-25 के अंतिम अनुमानों से 2.3 प्रतिशत अधिक है।

[14] 19 दिसंबर 2025 तक चावल की खरीद 281 लाख टन तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.8 प्रतिशत अधिक है।

चार्ट III.7: कृषि *खरीफ* फसल उत्पादन 2025-26: प्रथम अग्रिम अनुमान

(मिलियन टन, बायाँ मान, प्रतिशत, दायाँ मान)

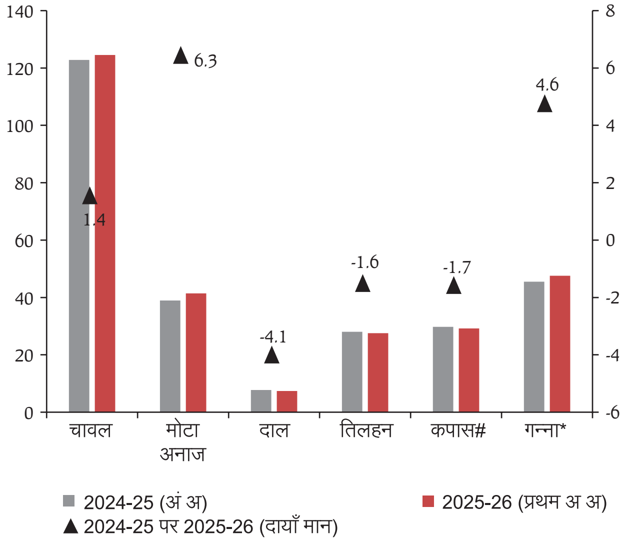

#: 170 किलोग्राम की मिलियन गाँठ *: गन्ना 10 मिलियन टन में है।
टिप्पणी: अं अ: अंतिम अनुमान , अ अ: अग्रिम अनुमान
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

चार्ट III.8: अधिक *रबी* बुवाई क्षेत्र

(लाख हेक्टयर, बायाँ मान, प्रतिशत, दायाँ मान)

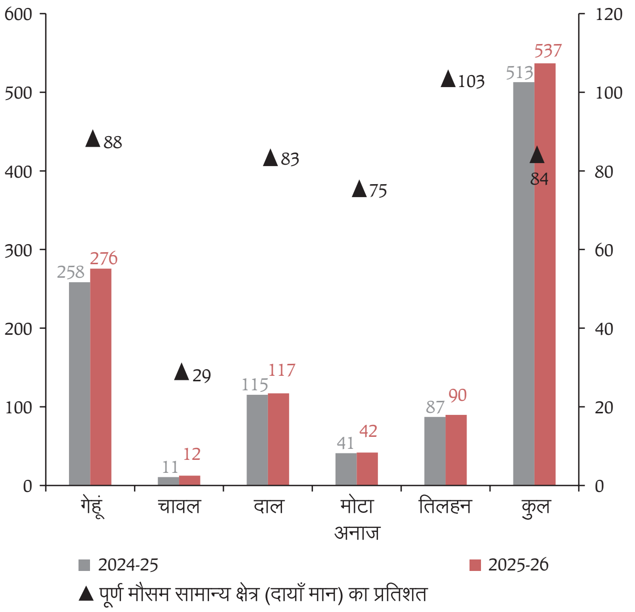

टिप्पणी: डेटा 12 दिसंबर तक के अनुसार है।
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नतीजतन, सरकार के पास चावल और गेहूं का कुल स्टॉक संतोषजनक स्थिति में है, जिसमें चावल का स्टॉक रिकॉर्ड ऊँचाई पर है।[15]

मानसून के बाद हुई अच्छी बारिश के कारण जलाशयों का जलस्तर ऊँचा है, जिससे रबी की चल रही बुवाई को मदद मिली है।[16] सभी प्रमुख फसलों के तहत बुवाई का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, जो रबी की फसल के लिए बेहतर संभावनाओं का संकेत देता है (चार्ट III.8)।[17]

औद्योगिक गतिविधि के मासिक संकेतक

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन के आधार पर मापी गई औद्योगिक गतिविधि में वृद्धि, अक्तूबर में 14 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई। इसकी मुख्य वजह विनिर्माण उत्पादन में आई सुस्ती थी, जो मुख्य रूप से काम के दिनों की संख्या कम होने के कारण हुई। अक्तूबर में खनन और विद्युत क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक अपरिवर्तित रहा, क्योंकि स्टील, सीमेंट, उर्वरक और रिफाइनरी उत्पादों में हुई वृद्धि की भरपाई कोयला, बिजली, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल में आई गिरावट से हो गई।

नवंबर के उच्च-आवृत्ति सूचकांक मजबूत औद्योगिक गतिविधि की ओर इशारा करते हैं। स्टील उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जो अवसंरचना और विनिर्माण गतिविधि में लगातार बनी हुई तेज़ी को दर्शाता है। नवंबर में ऑटोमोबाइल उत्पादन ने फरवरी 2024 के बाद से अपनी सबसे उच्च वृद्धि दर्ज की, जिसमें सभी खंडों में दोहरे अंकों में बढ़ोतरी हुई। अक्तूबर में गिरावट के बाद दो-पहिया वाहनों के उत्पादन में भी फिर से तेज़ी आई। स्थिर घरेलू मांग, और साथ में जीएसटी सुधारों ने इस क्षेत्र की मजबूत वृद्धि को बनाए रखा। पीएमआई विनिर्माण में, हालांकि लगातार मजबूत विस्तार देखने को मिल रहा है, लेकिन नए ऑर्डर और भविष्य के उत्पादन की

[15] 1 दिसंबर 2025 तक कुल स्टॉक 867 लाख टन था, जिसमें चावल का स्टॉक 575.7 लाख टन (बफर मानदंडों का 5.6 गुना) और गेहूं का स्टॉक 291.4 लाख टन (बफर आवश्यकता का 1.4 गुना) था।

[16] 18 दिसंबर 2025 तक, देश के 166 प्रमुख जलाशयों में औसत जल भंडारण स्तर अपनी पूर्ण क्षमता के 83 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 6.8 प्रतिशत और सामान्य भंडारण स्तर की तुलना में 21.9 प्रतिशत अधिक है।

[17] रबी फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र (12 दिसंबर तक) पूरे मौसम के सामान्य रकबे का 84 प्रतिशत है और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान बोए गए क्षेत्र से 4.7 प्रतिशत अधिक है।

सारणी III.4: उद्योग के लिए उच्च आवृत्ति संकेतकों में मजबूत वृद्धि दिखाई दी

सूचकांक	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्तू-25	नवं-25
आईआईपी-हेडलाइन	5.0	3.7	5.2	2.7	3.9	2.6	1.9	1.5	4.3	4.1	4.6	0.4	
आईआईपी-विनिर्माण	5.5	3.7	5.8	2.8	4.0	3.1	3.2	3.7	6.0	3.8	5.6	1.8	
आईआईपी-पूंजीगत वस्तु	8.9	10.5	10.2	8.2	3.6	14.0	13.3	3.0	6.8	4.5	5.4	2.4	
पीएमआई विनिर्माण	56.5	56.4	57.7	56.3	58.1	58.2	57.6	58.4	59.1	59.3	57.7	59.2	56.6
पीएमआई एक्सपोर्ट ऑर्डर	54.6	54.7	58.6	56.3	54.9	57.6	56.9	60.6	57.3	56.1	56.5	54.7	54.1
पीएमआई विनिर्माण, फ्यूचर आउटपुट	65.5	62.5	65.1	64.9	64.4	64.6	63.1	62.2	57.6	60.5	64.8	62.3	57.1
आठ प्रमुख सूचकांक	5.8	5.1	5.1	3.4	4.5	1.0	1.2	2.2	3.7	6.5	3.3	0.0	
विद्युत निर्माण: परंपरागत	2.6	4.5	-1.3	2.4	4.8	-1.8	-8.2	-6.1	-0.8	1.0	0.8	-10.6	-5.1
विद्युत निर्माण: नवीकरणीय	19.0	17.9	31.9	12.2	25.2	28.0	18.2	28.7	26.4	22.7	16.4	21.4	
ऑटोमोबाइल उत्पादन	8.0	1.3	9.4	2.3	6.5	-1.7	5.2	1.2	10.7	8.1	10.8	-2.8	22.3
यात्री वाहन उत्पादन	6.5	9.2	3.7	4.5	11.2	10.8	5.4	-1.8	0.1	-4.1	16.1	9.8	22.8
ट्रैक्टर उत्पादन	24.7	20.9	23.7	-7.8	18.5	20.5	9.1	9.8	11.5	9.4	23.0	13.0	37.5
दो-पहिए उत्पादन	8.8	-0.6	10.3	1.6	5.6	-4.1	4.7	1.4	12.3	10.0	9.8	-5.6	20.9
तीन-पहिए उत्पादन	-5.5	7.6	16.2	6.5	6.0	4.1	16.9	8.6	24.0	15.8	15.9	15.9	55.4
कच्चा इस्पात उत्पादन	4.5	8.3	7.4	6.0	8.5	9.3	11.0	12.6	13.8	12.8	13.2	9.4	11.8
तैयार इस्पात उत्पादन	2.8	5.3	6.7	6.7	10.0	6.6	7.0	10.9	13.8	13.8	13.8	10.0	13.5
पूंजीगत वस्तुओं का आयात	4.4	6.1	15.5	-0.5	8.6	24.5	15.7	3.4	13.3	0.2	12.8	8.7	13.1

<<संकुचन -- विस्तार >>

टिप्पणियाँ: 1. सभी संकेतकों (पीएमआई को छोड़कर) के लिए व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
2. हीट मैप प्रत्येक संकेतक की डेटा श्रेणी को कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदल देता है, जहां लाल निम्नतम मानों को दर्शाता है और हरा संबंधित डेटा शृंखला के उच्चतम मानों को दर्शाता है।
3. हीट मैप अप्रैल 2023 से नवीनतम माह (जहां तक डेटा उपलब्ध है) के डेटा पर लागू है।
4. सभी पीएमआई मानों को सूचकांक रूप में रिपोर्ट किया गया है। पीएमआई मान > 50 होने पर विस्तार, 50> होने पर संकुचन और =50 होने पर 'कोई परिवर्तन नहीं' का संकेत मिलता है। पीएमआई हीट मैप में लाल निम्नतम मान को दर्शाता है, पीला 50 (या अपरिवर्तित मान) को दर्शाता है, और हरा प्रत्येक पीएमआई शृंखला में उच्चतम मान को दर्शाता है।

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई); एस&पी ग्लोबल; केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफेक्चर्स (एसआईएएम); आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, भारत सरकार; संयुक्त संयंत्र समिति; वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय; और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; और ट्रैक्टर एंड मेकेनिजेशन असोशिएशन।

संभावनाओं में आई सुस्ती के कारण इसमें कुछ कमी दर्ज की गई (सारणी III.4)।

सेवा गतिविधियों के मासिक संकेतक

नवंबर में भारत के सेवा क्षेत्र में गतिविधियों में मजबूत विस्तार जारी रहा। खुदरा वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात मजबूत बने रहे। बंदरगाह कार्गो यातायात की वृद्धि दर में तेजी दर्ज की गई (सारणी III.5)।

क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (सीसीपीआई) रिपोर्ट 2026[18] ने भारत की रैंकिंग जी20 देशों में 5वें सबसे अच्छे देश के तौर पर की है (वैश्विक स्तर पर 23वीं रैंक), जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की मजबूत प्रगति को अभिस्वीकृत करता है। यह उल्लेखनीय है कि जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर भारत का अनुकूलन-संबंधी खर्च 2016-17 से 2022-23 तक 150 प्रतिशत तक काफी बढ़ गया है।[19] जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, भारत ने नवंबर 2025 में आयोजित 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ़ द पार्टीज़ (सीओपी30) में अनुकूलन के लिए अधिक वित्तपोषण की वकालत की।[20]

[18] जर्मनवॉच द्वारा 18 नवंबर 2025 को प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2026, 63 देशों और यूरोपीय संघ (ईयू) के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है और उनकी तुलना करती है।

[19] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2192347®=3&lang=2.

[20] संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार, विकासशील देशों के अनुकूलन वित्तपोषण में काफी कमी है। उन्हें 2035 तक प्रति वर्ष 310-365 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में केवल 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण हो रहा है।

सारणी III.5: सेवाओं के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक मजबूत रहे

सूचकांक	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सितं-25	अक्तू-25	नवं-25
पीएमआई सेवाएँ	58.4	59.3	56.5	59.0	58.5	58.7	58.8	60.4	60.5	62.9	60.9	58.9	59.8
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा ट्रेफिक	10.7	9.0	11.1	7.7	6.8	13.0	5.0	3.4	5.5	7.7	7.3	9.7	9.2
घरेलू हवाई मालवाहक	0.3	4.3	6.9	-2.5	4.9	16.6	2.3	2.6	4.8	7.1	2.8	-2.3	
अंतरराष्ट्रीय हवाई मालवाहक	16.1	10.5	7.1	-6.3	3.3	8.6	6.8	-1.2	4.2	4.5	2.3	-2.3	
बंदरगाह माल यातायात	-5.0	3.4	7.6	3.6	13.3	7.0	4.3	5.6	4.0	2.5	11.5	11.9	14.6
खुदरा वाणिज्यिक वाहन बिक्री	-9.3	-5.2	8.2	-8.6	2.7	-1.0	-3.7	6.6	0.2	8.6	2.7	21.1	19.9
होटल अधिभोग	11.1	-0.2	1.2	0.6	1.9	7.2	-2.8	-0.3	-2.4	-3.2	-0.6	0.0	
इस्पात खपत	9.5	5.2	10.9	10.9	13.6	6.0	8.1	9.3	7.3	10.0	8.9	4.7	7.1
सीमेंट उत्पादन	13.1	10.3	14.3	10.7	12.2	6.3	9.7	8.2	11.6	5.4	5.0	5.3	

<<संकुचन -- विस्तार>>

टिप्पणियाँ: 1. सभी संकेतकों (पीएमआई को छोड़कर) के लिए व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
2. हीट मैप प्रत्येक संकेतक की डेटा श्रेणी को कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदल देता है, जहां लाल निम्नतम मानों को दर्शाता है और हरा संबंधित डेटा शृंखला के उच्चतम मानों को दर्शाता है।
3. हीट मैप अप्रैल 2023 से नवीनतम माह (जहां तक डेटा उपलब्ध है) के डेटा पर लागू है।
4. नवंबर 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा ट्रेफिक की वृद्धि दर संबंधी डेटा दैनिक डेटा को जोड़कर निकाला गया है।
5. सभी पीएमआई मानों को सूचकांक रूप में रिपोर्ट किया गया है। पीएमआई मान > 50 होने पर विस्तार, 50> होने पर संकुचन और =50 होने पर 'कोई परिवर्तन नहीं' का संकेत मिलता है। पीएमआई हीट मैप में लाल सबसे निम्न मान को दर्शाता है, पीला 50 (या अपरिवर्तित मान) को दर्शाता है, और हरा प्रत्येक पीएमआई शृंखला में उच्चतम मान को दर्शाता है।

स्रोत: फेडेरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोशिएशन (एफएडीए); इंडियन पॉर्ट्स असोशिएशन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; एचवीएस एनारोक; संयुक्त संयंत्र समिति; आर्थिक सलाहकार का कार्यालय; और एस&पी ग्लोबल।

मुद्रास्फीति

नवंबर में हेडलाइन महंगाई[21] बढ़कर 0.7 प्रतिशत हो गई। इसकी वजह खाद्य कीमतों में अपस्फीति की दर का कम होना है। अक्तूबर में यह अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 0.3 प्रतिशत पर पहुँच गई थी(चार्ट III.9)।[22]

चार्ट III.9: खाद्य और ईंधन ने हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि को बढ़ावा दिया

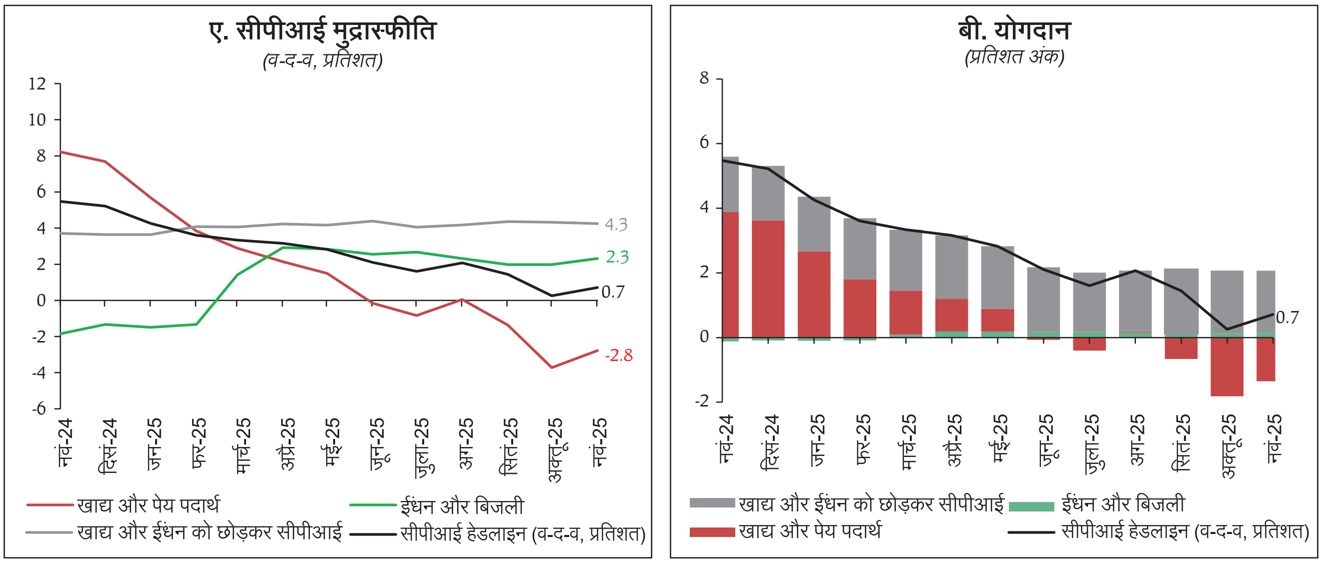

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ की गणना।

[21] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 12 दिसंबर 2025 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

[22] मुद्रास्फीति में लगभग 45 बीपीएस की वृद्धि लगभग 30 बीपीएस के गति प्रभाव और लगभग 15 बीपीएस के प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण हुई। यह सकारात्मक गति मुख्य रूप से खाद्य और ईंधन की कीमतों से प्रेरित थी।

चार्ट III.10: मुद्रास्फीति में वृद्धि के प्रमुख चालक: सब्जियों में अपस्फीति में कमी

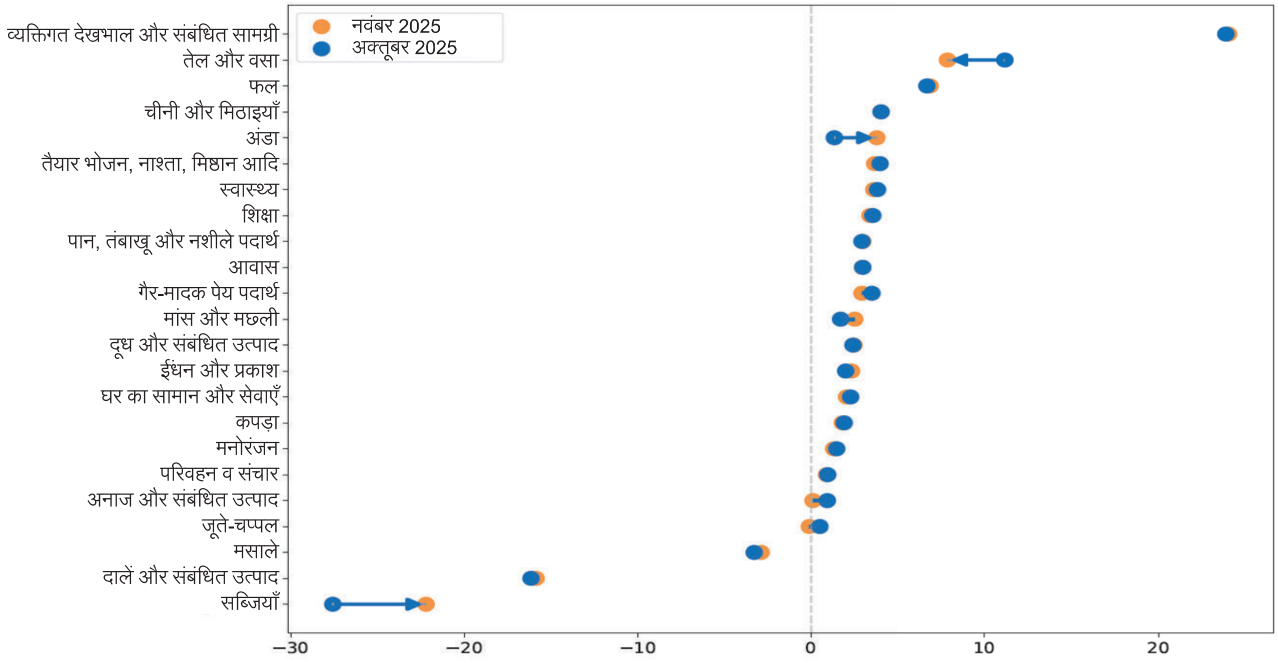

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान

खाद्य कीमतें लगातार तीसरे महीने अपस्फीति के दौर में रहीं, हालाँकि अपस्फीति की गति थोड़ी धीमी हुई।[23] खाद्य समूह के भीतर, सब्ज़ियों, दालों और मसालों की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर गिरावट आई। अनाज, तेल और वसा, तैयार भोजन और गैर-अल्कोहल वाले पेय जैसे उप-समूहों में मुद्रास्फीति कम हुई, जबकि मांस और मछली, अंडे, दूध और उससे बने उत्पादों, और फलों में मुद्रास्फीति दर बढ़ी (चार्ट III.10)।

अक्तूबर में 2.0 प्रतिशत रही ईंधन और प्रकाश की मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 2.3 प्रतिशत हो गई। इसका मुख्य कारण पीडीएस केरोसिन की कीमतें थीं, जो सात महीनों के बाद अपस्फीति से बाहर निकलीं। एलपीजी की मुद्रास्फीति का स्तर ऊँचा बना रहा।

नवंबर में मूल (यानी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर) मुद्रास्फीति 4.3 प्रतिशत पर स्थिर रही, जो अक्तूबर के स्तर के बराबर थी। कपड़े और जूते, स्वास्थ्य, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, शिक्षा और घरेलू सामान और सेवाओं के उप-समूहों में मुद्रास्फीति कम हुई, जबकि पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों, तथा व्यक्तिगत देखभाल और संबंधित सामान के उप-समूहों में मुद्रास्फीति बढ़ गई। कीमती धातुओं को छोड़कर, मूल मुद्रास्फीति 2.4 प्रतिशत पर थी।

नवंबर में शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़ी, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह अपस्फीति से बाहर निकल आई।[24] राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, मुद्रास्फीति (-) 4.2 प्रतिशत से 8.3 प्रतिशत के बीच अलग-अलग रही, और ज़्यादातर राज्यों में मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत से नीचे ही दर्ज की गई। कुल मिलाकर, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति का दबाव कम रहा। हालाँकि, 37 में से 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी दर्ज की गई (चार्ट III.11)।

दिसंबर महीने के लिए अब तक (19 तारीख तक) खाद्य-कीमतों के डेटा से पता चलता है कि अनाज की कीमतों में तेजी आई है। दालों में, चने की कीमतें कम हुईं, जबकि तुअर/अरहर दाल की कीमतें बढ़ गईं। मूंग की कीमतें स्थिर रहीं। खाद्य-तेलों में, सूरजमुखी तेल और मूंगफली तेल की कीमतें बढ़ गईं। सरसों-तेल की कीमतें स्थिर रहीं। टमाटर और प्याज की कीमतों में तेजी आई और आलू की कीमतें कम हुईं (चार्ट III.12)।

[23] खाद्य पदार्थों की अपस्फीति नवंबर में घटकर 2.8 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने 3.7 प्रतिशत थी।

[24] शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति क्रमशः 1.4 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत थी।

चार्ट III.11 विभिन्न राज्यों में नवंबर में मुद्रास्फीति में सामान्य वृद्धि

(व-द-व, प्रतिशत)

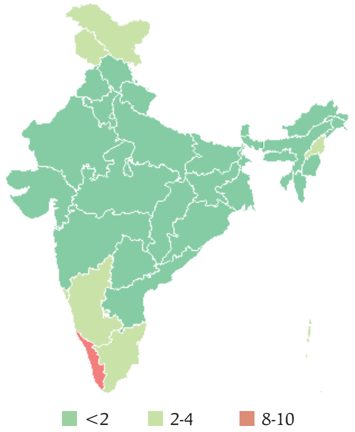

मुद्रास्फीति सीमा	राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या
<2	27
2-4	8
4-6	0
6-8	0
8-10	2
मुद्रास्फीति रुख	**राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या**
कमी या स्थिर	12
बढ़ोतरी	25

टिप्पणियाँ: 1. मैप केवल उदाहरण के लिए है।
2. केरल और लक्षद्वीप में मुद्रास्फीति 8 प्रतिशत से अधिक है।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

दिसंबर में पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की खुदरा बिक्री कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जबकि सब्सिडी वाले केरोसिन की कीमतों में वृद्धि हुई (19 तारीख तक) [सारणी III.6]।

सारणी III.6: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

मद	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		दिसं-24	नवं-25	दिसं-25^	नवं-25	दिसं-25^
पेट्रोल	₹/लीटर	101.02	101.12	101.13	0.00	0.01
डीज़ल	₹/लीटर	90.48	90.53	90.53	0.00	0.00
केरोसिन (रियायती)	₹/लीटर	44.75	45.91	48.64	1.24	5.95
एलपीजी (रियायती)	₹/सिलिंडर	813.3	863.3	863.3	0.0	0.0

^ :1-19 दिसंबर, 2025 की अवधि के लिए।
टिप्पणी: केरोसिन के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। केरोसिन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।
स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

नवंबर में, विनिर्माण पीएमआई में इनपुट और आउटपुट, दोनों कीमतों में वृद्धि-दर में नरमी दर्ज की गई। इस महीने के

चार्ट III.12: खाद्य कीमतों में दिसम्बर में मामूली वृद्धि दर्ज हुई

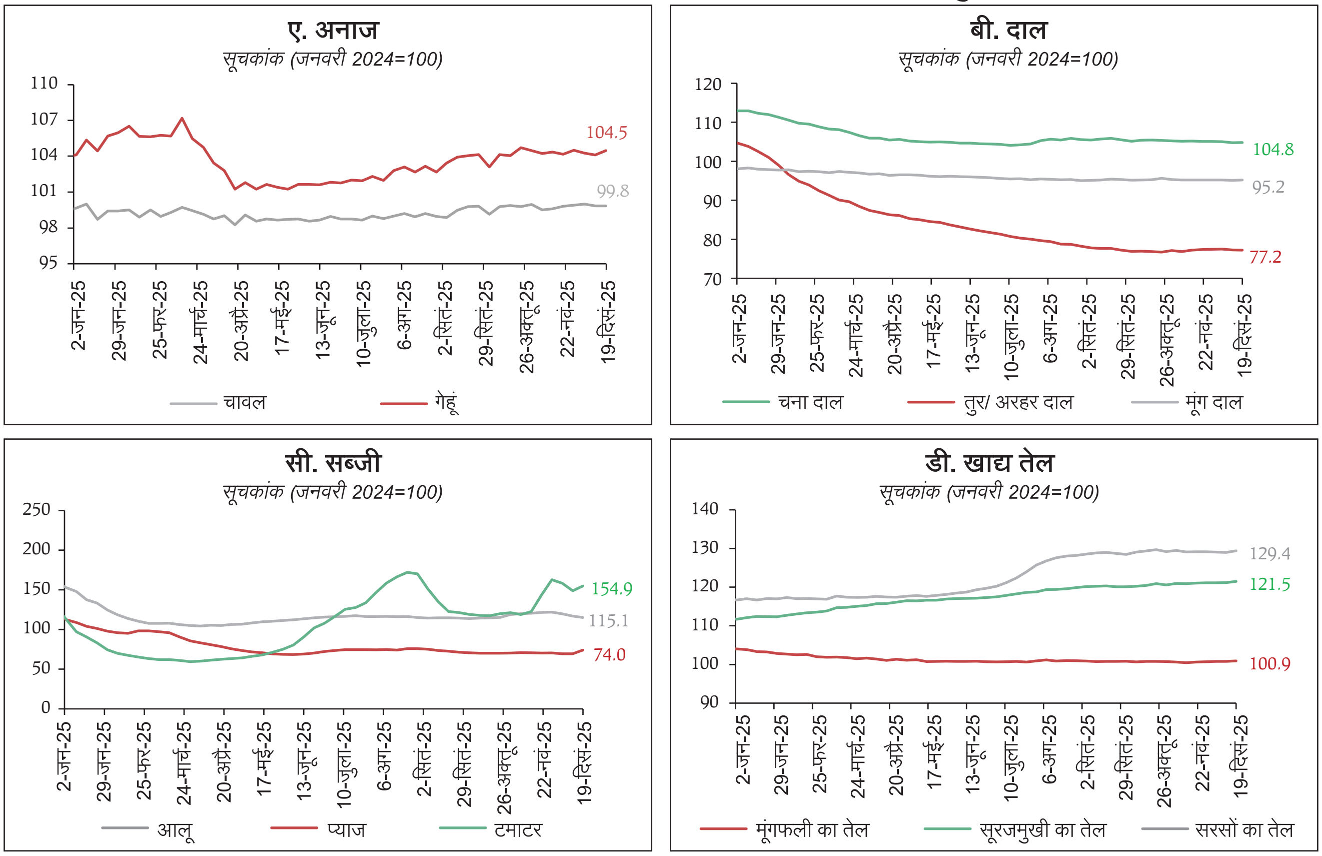

टिप्पणी: डेटा साप्ताहिक औसत से संबंधित है।
स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट III.13: विनिर्माण और सेवा फ़र्मों दोनों के लिए इनपुट और आउटपुट कीमत विस्तार की गति में कमी

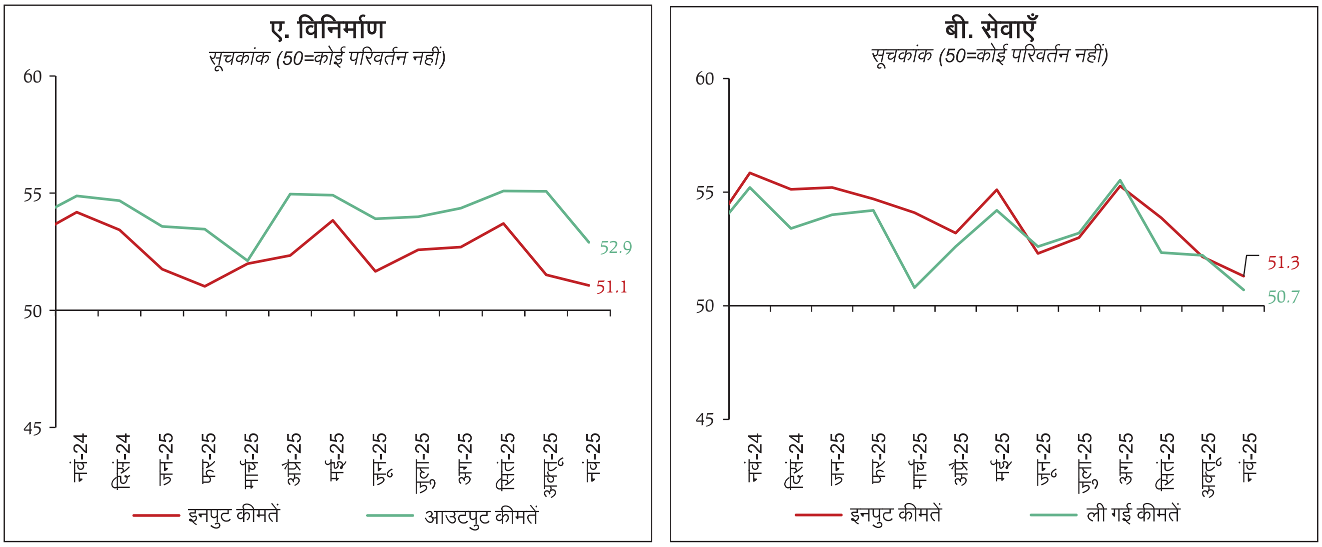

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार और उसके विपरीत को दर्शाती है।
स्रोत: एस&पी

दौरान मुद्रास्फीति कम रहने से कंपनियों पर इनपुट लागत का दबाव कम रहा, जिससे वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी कीमतें बनाए रखने के लिए कंपनियों ने अपनी बिक्री कीमतों में भी सीमित बढ़ोतरी की। सेवाओं के पीएमआई में भी, लागत का दबाव कम होने और कंपनियों द्वारा नया कारोबार हासिल करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप, इनपुट कीमतों और बिक्री कीमतों, दोनों में ही गिरावट जारी रही (चार्ट III.13)।

IV. वित्तीय स्थितियाँ

कुल मिलाकर वित्तीय स्थितियाँ अनुकूल बनी रहीं, हालाँकि नवंबर के दूसरे पखवाड़े से जी-सेक बाजार को छोड़कर अन्य सभी बाजार खंडों में तंगी देखने को मिली (चार्ट IV.1)।

नवंबर के दूसरे पखवाड़े और दिसंबर (19 तारीख तक) के दौरान बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि ज़्यादातर अधिशेष में रही।

चार्ट IV.1: सौम्य दैनिक वित्तीय स्थिति सूचकांक

(2012 से औसत से मानक विचलन)

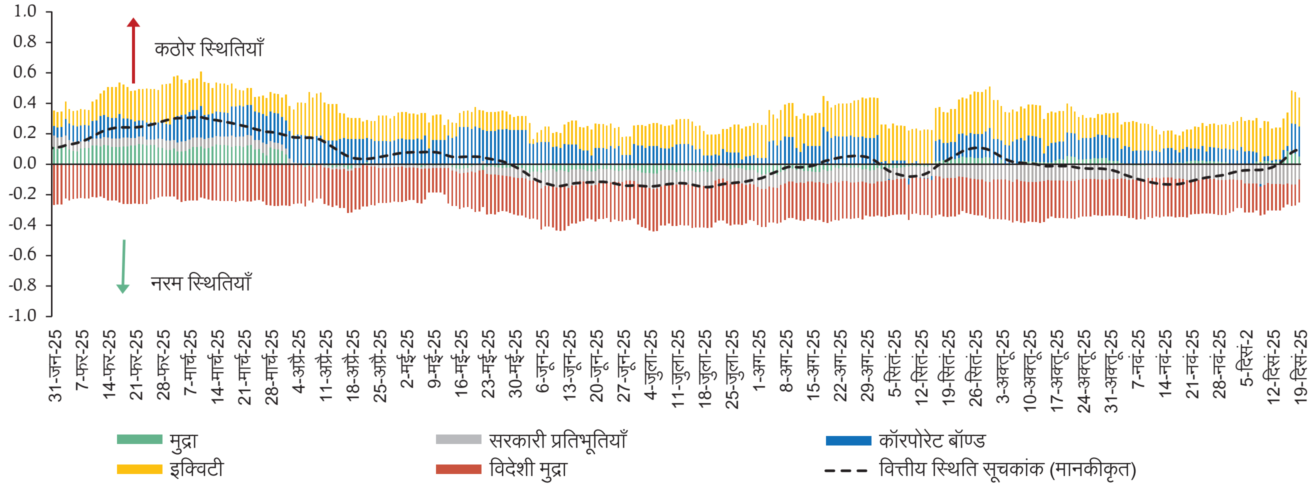

टिप्पणी: वित्तीय स्थिति सूचकांक अपने ऐतिहासिक औसत के आधार पर एक मेट्रिक देता है; इस मामले में, शून्य मान उस वित्तीय प्रणाली से मेल खाती है जो सूचकांक में शामिल सभी वित्तीय सूचकांकों के ऐतिहासिक औसत स्तर पर काम कर रहा है। परिणाम प्रस्तुत करने के लिए, माननीकृत सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

[25] विस्तृत कार्यप्रणाली के लिए https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=23451 देखें।

जीएसटी से जुड़े भुगतान के चलते सरकारी नकदी शेष में हुई अस्थायी बढ़ोतरी और संचलन में मौजूद मुद्रा में हुई बढ़ोतरी के कारण नवंबर के दूसरे पखवाड़े में प्रणालीगत चलनिधि में कुछ कमी आई। सीआरआर में कटौती की आखिरी शृंखला, जो 29 नवंबर, 2025 से लागू हुई, ने दिसंबर के मध्य तक चलनिधि की स्थिति में सुधार किया। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े (19 तारीख तक) में, अग्रिम कर भुगतान के चलते सरकारी नकदी शेष में हुई बढ़ोतरी के कारण प्रणालीगत चलनिधि घाटे में चली गई। चलनिधि की इस अस्थायी कमी को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने परिवर्ती दर रेपो नीलामी आयोजित की। प्रणाली में स्थायी चलनिधि इंजेक्ट करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने दिसंबर में ₹1 लाख करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) खरीद की और यूएसडी 5 बिलियन के 3-वर्षीय यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री/ स्वैप आयोजित किए।[26]

कुल मिलाकर, चलनिधि समाशोधन सुविधा के तहत औसत निवल अवशोषण 16 नवंबर से 19 दिसंबर के दौरान बढ़कर ₹1.63 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले एक महीने की अवधि में ₹1.2 लाख करोड़ था (चार्ट IV.2)। दिसंबर के पहले पखवाड़े में कुल चलनिधि स्थितियों में सुधार के साथ, बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने के लिए अलग-अलग परिपक्वता वाले 3-दिवसीय वीआरआरआर आयोजित किए गए। स्थायी जमा सुविधा के तहत औसत जमा-शेष थोड़ा ज्यादा रहा, और बैंकों द्वारा सीमांत स्थायी सुविधा का उपयोग अपरिवर्तित रहा।[27]

मुद्रा बाज़ार

नवंबर के दूसरे पखवाड़े में चलनिधि की अस्थायी कमी के बावजूद, भारित औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर) व्यापक तौर पर नीतिगत रेपो दर के अनुरूप रही। दिसंबर की शुरुआत से चलनिधि-स्थिति में सुधार होने के कारण डबल्यूएसीआर नीतिगत कॉरिडोर के दायरे में ही रही, हालांकि दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में चलनिधि- तंगी के कारण इसमें कुछ कठोरता देखने को मिली। 16 नवंबर से 19 दिसंबर के दौरान, नीतिगत रेपो दर के मुकाबले डबल्यूएसीआर का स्प्रेड औसतन अपरिवर्तित रहा, जबकि पिछले एक महीने की अवधि में इसमें बदलाव देखा गया था (चार्ट IV.3ए)। संपार्श्विक खंड में एकदिवसीय

चार्ट IV.2 : चलनिधि की अच्छी स्थितियाँ

(₹ लाख करोड़)

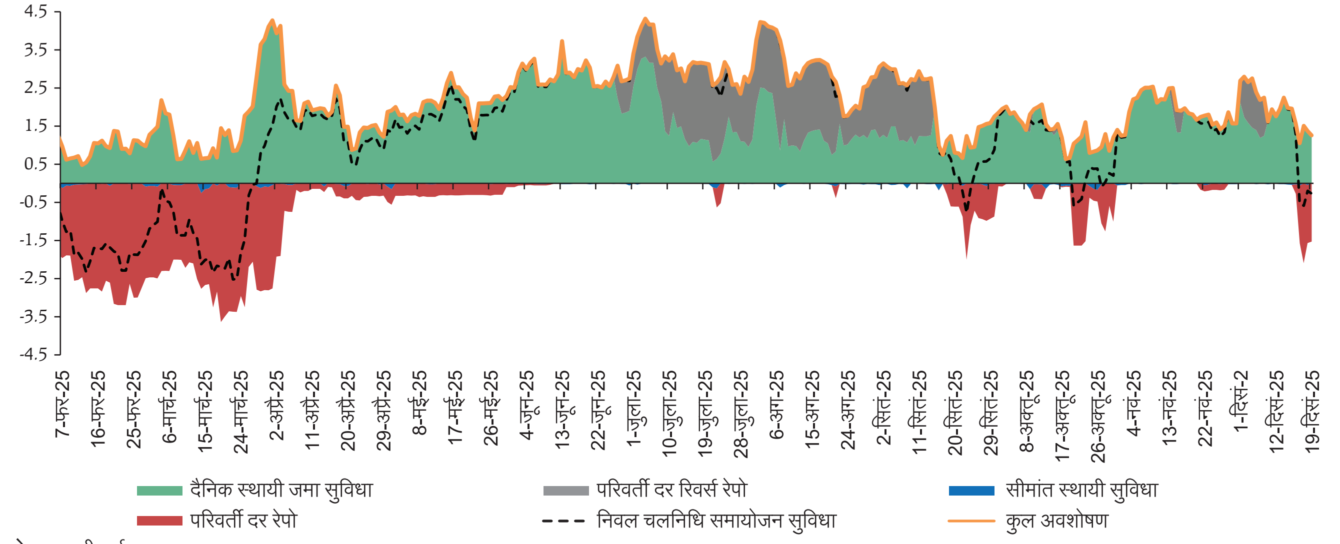

स्रोत: आरबीआई।

---

[26] ओएमओ खरीद नीलामी 11 दिसंबर और 18 दिसंबर को दो बराबर शृंखलाओं में आयोजित की गई, प्रत्येक शृंखला की राशि ₹50,000 करोड़ थी। तीन वर्षीय यूएसडी/आईएनआर खरीद-बिक्री स्वैप नीलामी 16 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई।

[27] स्थायी जमा सुविधा के अंतर्गत औसत शेष राशि 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान मामूली रूप से बढ़कर 1.64 लाख करोड़ रुपये हो गई, जबकि इससे पहले की एक माह की अवधि में यह 1.56 लाख करोड़ रुपये थी। इस अवधि के दौरान सीमांत स्थायी सुविधा से औसत उधार 0.02 लाख करोड़ रुपये रहा।

दर – जो संरक्षित एकदिवसीय रुपया दर से मापी जाती है – बिना संपार्श्विक दर के अनुरूप रही। तीन महीने के ट्रेजरी बिलों पर प्रतिफल में नरमी आई, जो नीतिगत रेपो दर में कटौती और चलनिधि की बेहतर स्थिति को दर्शाता है। साथ ही, एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए जमा-प्रमाणपत्र और 3-महीने के वाणिज्यिक पत्र पर ब्याज दरें मोटे तौर पर स्थिर रहीं (चार्ट IV.3बी)। मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3-महीने के वाणिज्यिक पत्र और 91-दिन के ट्रेजरी बिल पर प्रतिफल के बीच का अंतर) में बढ़ोतरी दर्ज की गई।[28]

सरकारी प्रतिभूतियाँ (जी-सेक) बाजार

निश्चित आय क्षेत्र में, नीतिगत दर में कटौती और रिज़र्व बैंक के चलनिधि बढ़ाने संबंधी उपायों की घोषणा के दिन जी-सेक प्रतिफल में नरमी आई। उसके बाद, मौजूदा नरमी के दौर के खत्म होने की बाजार की धारणाओं के बीच प्रतिफल में वृद्धि हुई। हालाँकि, 11 और 18 दिसंबर 2025[29] को आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद के बाद प्रतिफल में मामूली नरमी आई। एक महीने पहले की तुलना में, प्रतिफल वक्र (19 दिसंबर तक), खासकर वक्र के बीच वाले हिस्से में, ऊपर की ओर खिसक गया । इस दौरान टर्म स्प्रेड (10-वर्षीय जी-सेक और 91-दिवसीय ट्रेजरी बिल के प्रतिफल के बीच का अंतर) में मामूली बढ़ोतरी हुई (चार्ट IV.4ए और IV.4बी)[30]।

कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार

कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल और उनके स्प्रेड में, विविध रेटिंग और अवधि के आधार पर आम तौर पर मिले-जुले रुझान देखने को मिले (सारणी IV.1)। अक्तूबर में नए कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गम में मामूली बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर, मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक निर्गमित कुल बॉण्ड, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ज्यादा रहे।[31]

चार्ट IV.3: मुद्रा बाजार दरें व्यापक रूप से स्थिर रहीं

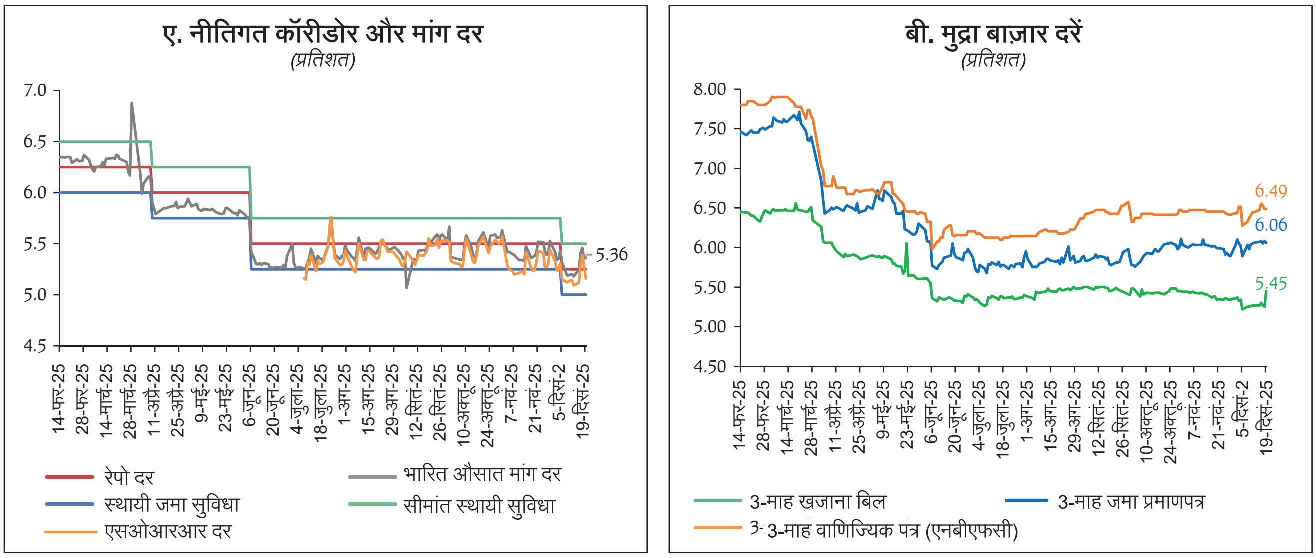

स्रोत: आरबीआई; और ब्लूमबर्ग।

[28] 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान यह बढ़कर 112 बीपीएस हो गया, जबकि इससे पहले की एक महीने की अवधि में यह 101 बीपीएस था।

[29] 10 वर्षीय बेंचमार्क जी-सेक (6.48 प्रतिशत जीएस 2035) पर प्रतिफल 10 दिसंबर को बढ़कर 6.63 प्रतिशत पर उच्च स्तर पर पहुंच गया, लेकिन आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद के बाद 18 दिसंबर को घटकर 6.57 प्रतिशत हो गया, जबकि 14 नवंबर को यह 6.49 प्रतिशत था।

[30] 10 वर्षीय जी-सेक और 91-दिवसीय ट्रेजरी बिल के बीच औसत अवधि स्प्रेड 16 नवंबर से 19 दिसंबर के दौरान 16 अक्तूबर से 15 नवंबर की अवधि की तुलना में 13 बीपीएस बढ़ गया।

[31] अक्तूबर 2025 में यह बढ़कर ₹0.79 लाख करोड़ हो गया, जबकि सितंबर 2025 में यह ₹0.74 लाख करोड़ था। संचयी आधार पर (अप्रैल से अक्तूबर तक), यह 2025-26 में ₹5.5 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹5.4 लाख करोड़ था।

चार्ट IV.4: जी-सेक प्रतिफल को स्थिर करना

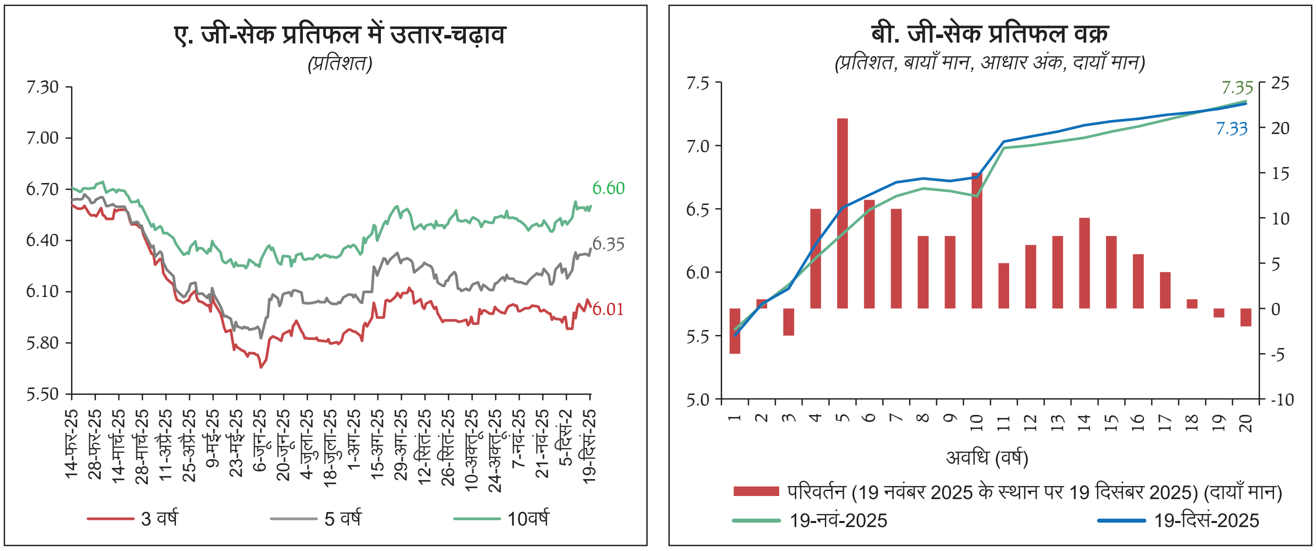

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

मुद्रा और ऋण

नवंबर और दिसंबर में अब तक (12 तारीख तक), आरक्षित निधि (सीआरआर के लिए समायोजित) में वृद्धि, संचलन में मौजूद मुद्रा में वृद्धि के साथ-साथ हुई।[32] संचलन में मौजूद मुद्रा में यह तेज़ी चल रही मौसमी मांग की वजह से आई, जो आम तौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में देखने को मिलती है। मुद्रा आपूर्ति (एम3) में भी कुल जमा और जनता के पास मौजूद मुद्रा के चलते तीव्र गति से वृद्धि हुई (चार्ट IV.5)।[33]

5 सितंबर से अलग-अलग चरणों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कुल 100 आधार अंकों की संचयी कटौती के साथ, पिछले तीन महीनों में बैंकों का आरक्षित निधि-जमा अनुपात कम हो गया, जिसके चलते मुद्रा गुणक[34] में वृद्धि हुई (चार्ट IV.6)।

सारणी IV.1: कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल और स्प्रेड सामान्य तौर पर नरम हुए

लिखत	ब्याज दर *(प्रतिशत)*			स्प्रेड *(बीपीएस)* (संबंधित जोखिम-मुक्त दर पर)		
	अक्तूबर 16, 2025 – नवंबर 17, 2025	नवंबर 18, 2025 – दिसंबर 17, 2025	अंतर *(बीपीएस)*	अक्तूबर 16, 2025 – नवंबर 17, 2025	नवंबर 18, 2025 – दिसंबर 17, 2025	अंतर
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
(i) एएए (1-वर्ष)	6.70	6.85	15	107	127	20
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.03	7.03	0	105	109	4
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.22	7.18	-4	87	77	-10
(iv) एए (3-वर्ष)	8.10	8.03	-7	211	209	-2
(v) बीबीबी- (3-वर्ष)	11.79	11.68	-11	574	574	0

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के लिए औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: एफआईएमएमडीए

[32] आरक्षित निधि (नकदी आरक्षित अनुपात में परिवर्तनों के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित) और प्रचलन में मुद्रा में 12 दिसंबर 2025 तक क्रमशः 9.4 प्रतिशत और 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पहले क्रमशः 6.3 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत थी।

[33] 28 नवंबर 2025 को मुद्रा आपूर्ति में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले यह वृद्धि 9.7 प्रतिशत थी।

[34] मुद्रा गुणक को मुद्रा आपूर्ति और आरक्षित मुद्रा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।

चार्ट IV.5: आरक्षित मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति (एम3) में वृद्धि में तेजी आई

(व-द-व, प्रतिशत)

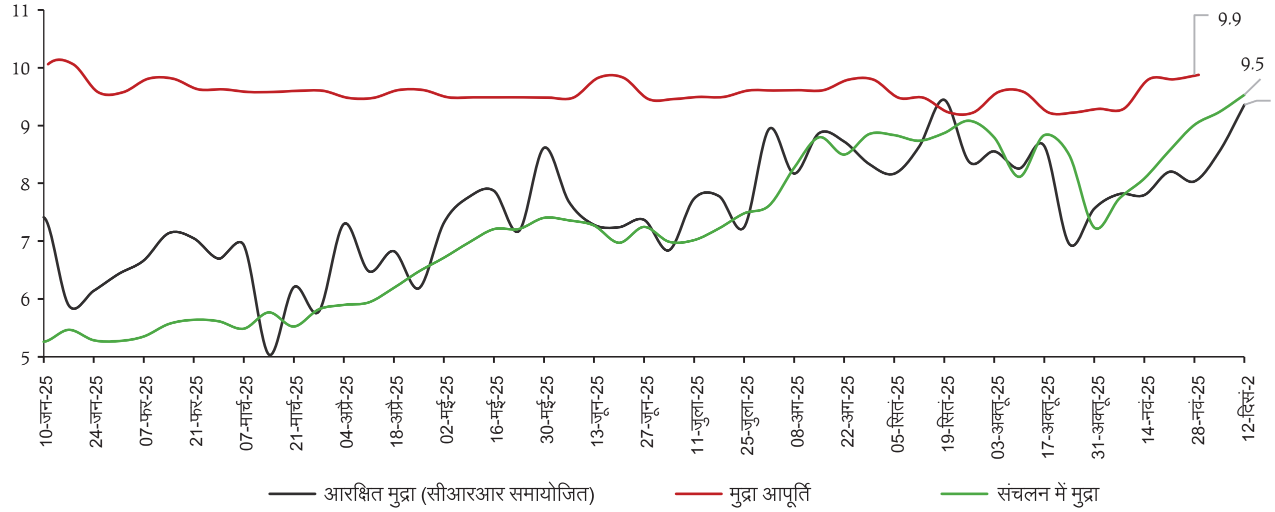

स्रोत: आरबीआई।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में ऋण वृद्धि में नवंबर (28 तारीख तक) के दौरान गति बनी रही [चार्ट IV.7]।[35] दूसरी ओर, बैंक जमाओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। परिणामस्वरूप, ऋण और जमा वृद्धि के बीच का अंतर अक्तूबर के अंत के 1.5 प्रतिशत अंक से घटकर नवंबर के अंत में 1.3 प्रतिशत अंक रह गया।

2025-26 के दौरान अब तक (28 नवंबर तक), वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह मजबूत बना रहा, जिसे गैर-बैंक मध्यस्थता में हुई वृद्धि से समर्थन प्राप्त हुआ। गैर-बैंक स्रोतों - कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गम और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश - में इस वर्ष में अब तक उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई (सारणी IV.ए)। 28 नवंबर तक, वाणिज्यिक क्षेत्र

चार्ट IV.6: मुद्रा गुणक में निरंतर वृद्धि

(अनुपात, प्रतिशत)

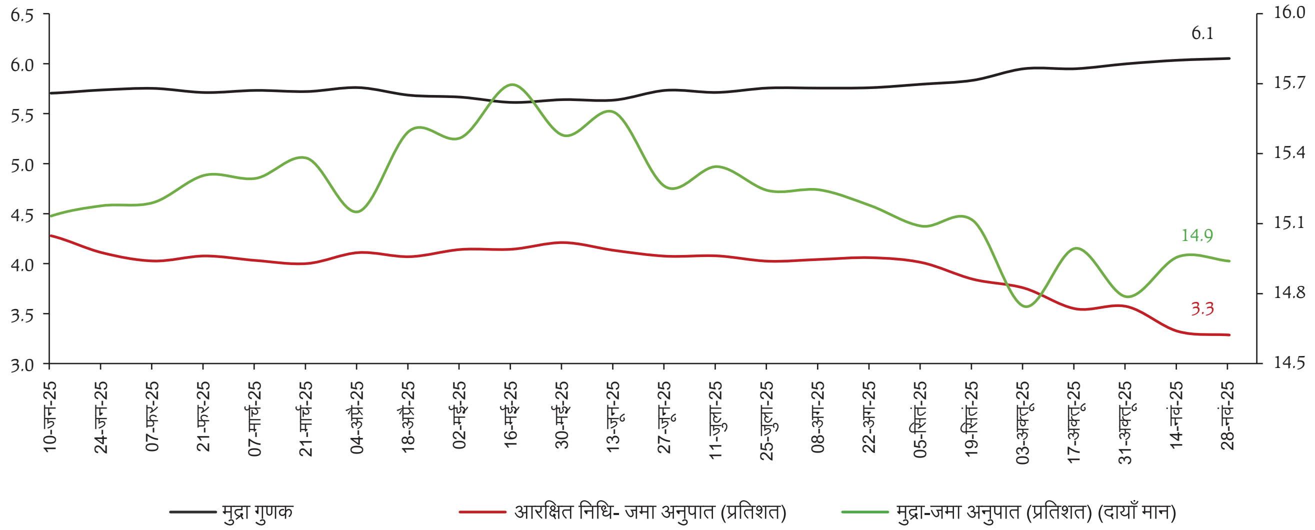

स्रोत: आरबीआई।

[35] 28 नवंबर 2025 तक की ऋण और जमा वृद्धि क्रमशः 11.5 प्रतिशत और 10.2 प्रतिशत रही।

चार्ट IV.7: ऋण विस्तार स्थिर, जमा वृद्धि में बढ़ोतरी

(व-द-व, प्रतिशत)

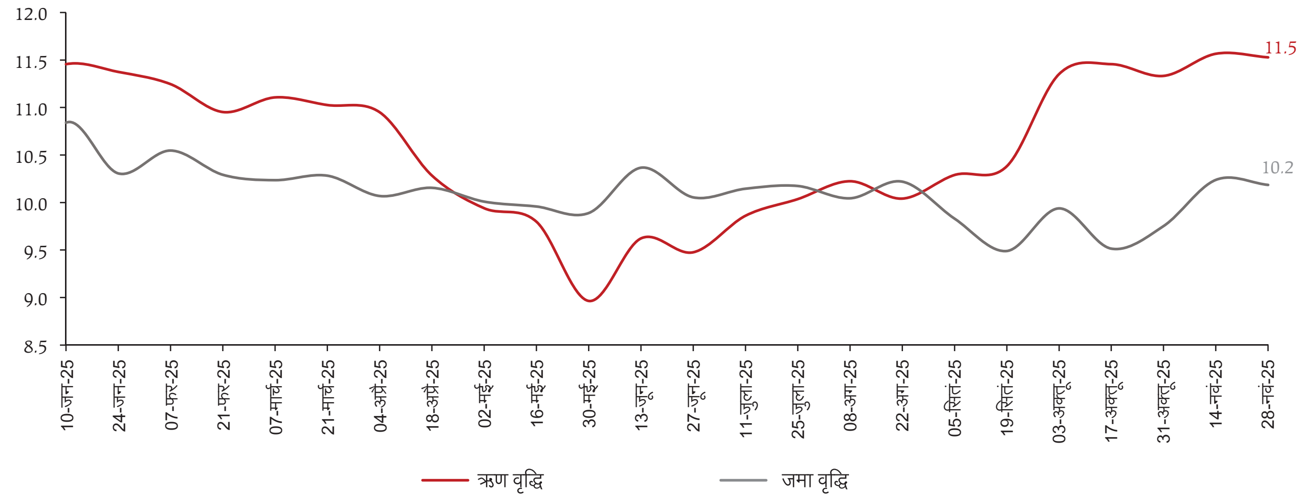

टिप्पणी: एससीबी के डेटा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का डेटा शामिल है। डेटा में एक गैर-बैंक का एक बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।
स्रोत: पाक्षिक सेक्शन 42 रिटर्न्स, आरबीआई।

को दिए गए कुल बकाया ऋण में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि गैर-बैंक स्रोतों में 17.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (सारणी IV.2बी)।

अक्तूबर में प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से उद्योग, सेवा और व्यक्तिगत ऋणों में बैंक ऋण वृद्धि मजबूत हुई (चार्ट IV.8)।[36] औद्योगिक ऋण वृद्धि में तेजी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिए गए ऋण में मजबूत वृद्धि के कारण हुई। सेवा क्षेत्र को दिए गए ऋण में बैंकों द्वारा गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) को दिए गए ऋण में भारी वृद्धि के कारण दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। व्यक्तिगत ऋणों में आवास और वाहन ऋणों के चलते वृद्धि हुई। उल्लेखनीय रूप से, सोने के आभूषणों के बदले दिए गए ऋणों में तेजी आई है और इसमें फरवरी 2025 से लगातार तिहरे अंकों की वृद्धि की जा रही है। इस तीव्र विस्तार का कारण सोने की कीमतों में उछाल हो सकता है। उच्च विकास दर के बावजूद, कुल गैर-खाद्य ऋण

सारणी IV.2ए: वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

(₹ करोड़)

स्रोत	अप्रैल-मार्च		28 नवंबर तक	
	2023-24	2024-25	2024-25	2025-26 P
ए. गैर-खाद्य बैंक ऋण	**21,40,243**	**17,98,321**	**10,48,619**	**12,40,071**
बी. गैर-बैंक स्रोत (बी1+बी2)	**12,63,721**	**17,10,457**	**7,86,083**	**10,16,620**
बी1. घरेलू स्रोत	10,20,302	13,85,609	5,85,742	7,48,761
बी2. विदेशी स्रोत	2,43,419	3,24,848	2,00,341	2,67,859
सी. संसाधनों का कुल प्रवाह (ए+बी)	**34,03,964**	**35,08,778**	**18,34,702**	**22,56,691**

अ: अनंतिम
टिप्पणी: विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया वर्तमान सांख्यिकी सारणी सं: 18(ए) देखें।
स्रोत: आरबीआई; सेबी; और एआईएफआई

सारणी IV.2बी: वाणिज्यिक क्षेत्र को बकाया ऋण

(₹ करोड़; कोष्ठक में आंकड़े व-द-व प्रतिशत परिवर्तन हैं)

स्रोत	मार्च की समाप्ति पर		नवंबर 28 के अनुसार	
	2024	2025	2024	2025 P
ए. गैर-खाद्य बैंक ऋण	**1,64,09,083 (20.2)**	**1,82,07,441 (11.0)**	**1,74,57,702 (10.6)**	**1,94,47,512 (11.4)**
बी. गैर-बैंक स्रोत (बी1+बी2)	**77,56,314 (4.2)**	**88,85,434 (14.6)**	**81,96,473 (12.2)**	**95,90,566 (17.0)**
बी1. घरेलू स्रोत	56,59,037 (4.9)	66,37,411 (17.3)	60,08,758 (15.6)	71,98,292 (19.8)
बी2. विदेशी स्रोत	20,97,277 (2.4)	22,48,023 (7.2)	21,87,714 (3.8)	23,92,274 (9.4)
सी. कुल ऋण (ए+बी)	**2,41,65,397 (14.5)**	**2,70,92,875 (12.1)**	**2,56,54,175 (11.1)**	**2,90,38,078 (13.2)**

अ: अनंतिम
टिप्पणी: विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया वर्तमान सांख्यिकी सारणी सं: 18(बी) देखें।
स्रोत: आरबीआई; सेबी; और एआईएफआई।

[36] क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण के लगभग 95 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले चुनिंदा बैंक शामिल हैं, और यह डेटा महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित है। डेटा अनंतिम है। एसआईबीसी रिटर्न के अंतर्गत आने वाले बैंक समूह हैं - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और लघु वित्त बैंक। डेटा में किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

चार्ट IV.8: प्रमुख क्षेत्रों में बैंक ऋण वृद्धि मजबूत हुई

(व-द-व, प्रतिशत)

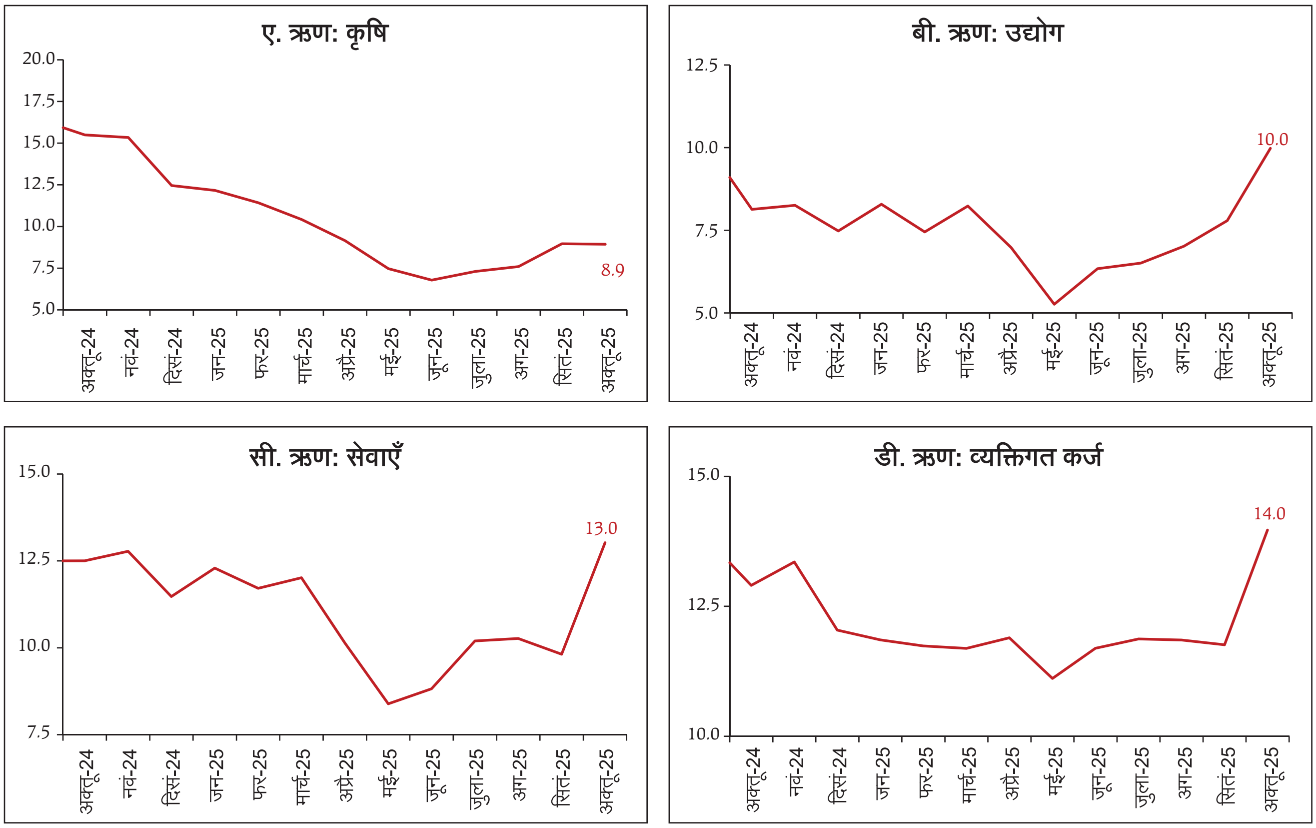

टिप्पणी: फरवरी से अगस्त 2025 के दौरान संचरण की गणना अगस्त 2025 की भारित औसत उधार और जमा दरों से जनवरी 2025 की भारित औसत उधार और जमा दरों को घटाकर की गई है।
स्रोत : आरबीआई।

में स्वर्ण ऋण का हिस्सा अपेक्षाकृत कम बना हुआ है, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है।[37]

जमा और ऋण दरें

फरवरी-अक्तूबर 2025 के दौरान नीतिगत रेपो दर में संचयी 100 आधार अंकों की कमी की प्रतिक्रिया में, बैंकों ने रेपो दर से जुड़े नए ऋणों पर अपनी बाहरी बेंचमार्क-आधारित ऋण दरों को भी इसी अनुपात में कम कर दिया है। इस अवधि के दौरान नए और बकाया रुपये ऋणों पर भारित औसत ऋण दरों में भी कमी आई है। जमा पक्ष पर, बैंकों ने नई सावधि जमाओं पर ब्याज दरों में उल्लेखनीय कमी की है। बकाया जमाओं की ब्याज दरों में यह कमी धीरे-धीरे हुई, जो निश्चित दरों पर सावधि जमाओं की लंबी अवधि के प्रभाव को दर्शाती है (सारणी IV.3)।

नए और बकाया रुपये के ऋणों पर भारित औसत उधार दर में गिरावट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी बैंकों के मामले में अधिक थी (चार्ट IV.9)। जमा पक्ष पर, नए सावधि जमा के मामले में निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए संचरण अधिक था।

इक्विटी बाजार

भारतीय इक्विटी बाजारों में नवंबर के पहले पखवाड़े में तेजी देखी गई और उसके बाद इनमें दोनों दिशाओं में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि, 2025-26 की दूसरी तिमाही

[37]अक्तूबर 2025 में कुल गैर-खाद्य ऋण में स्वर्ण ऋण का हिस्सा 1.8 प्रतिशत था, जबकि अक्तूबर 2024 में यह 0.9 प्रतिशत था। व्यक्तिगत ऋणों में स्वर्ण ऋण का हिस्सा अक्तूबर 2025 में 5.2 प्रतिशत था।

सारणी IV.3: बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंक)

		सावधि जमा दरें		ऋण दरें				
अवधि	रेपो दर	डबल्यूएडी टीडीआर-नए जमा	डबल्यूएडी टीडीआर-बकाया जमा	ईबीएलआर	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	डबल्यूएएलआर-नए रुपए ऋण		डबल्यूए एलआर-बकाया रुपया ऋण
						समग्र	ब्याज दर प्रभाव #	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
कठोर अवधि मई 2022 से जनवरी 2025	250	259	206	250	175	182	191	115
नरम अवधि फर 2025 से अक्तू*2025	-100	-105	-32	-100	-50	-69	-78	-63

*: एमसीएलआर का डेटा नवंबर 2025 के अनुसार है। #: जनवरी 2025 के भार के अनुसार गणना की गई है।
डबल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर; डबल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर।
एमसीएलआर: निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर; ईबीएलआर: बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर।
टिप्पणी: ईबीएलआर पर डेटा 32 घरेलू बैंकों से संबंधित है।
स्रोत: आरबीआई।

के अच्छे कॉरपोरेट परिणामों और रिज़र्व बैंक और यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती से इक्विटी बाजारों को समर्थन मिला, लेकिन भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता शेयरों के मूल्यांकन को लेकर नकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह में कमी ने बाजार की भावनाओं पर दबाव डाला। घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) इक्विटी बाजारों में निवल खरीदार बने रहे, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) निवल विक्रेता बन गए (चार्ट IV.10)।

बाह्य वित्त स्रोत

अप्रैल-अक्तूबर 2025 के दौरान, सकल और निवल दोनों ही दृष्टियों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा। अक्तूबर में सकल आवक एफडीआई स्थिर रहा, जिसमें सिंगापुर, मॉरीशस और यूएस का कुल एफडीआई प्रवाह में 70 प्रतिशत से अधिक का योगदान रहा (चार्ट IV.11ए)। एफडीआई प्रवाह के सबसे अधिक प्राप्तकर्ता (लगभग 60 प्रतिशत) वित्तीय सेवा क्षेत्र रहे। इसके बाद विनिर्माण, विद्युत और संचार सेवाओं का स्थान रहा। हालांकि,

चार्ट IV.9: बैंक समूहों के बीच संचरण (फरवरी -अक्तूबर 2025)

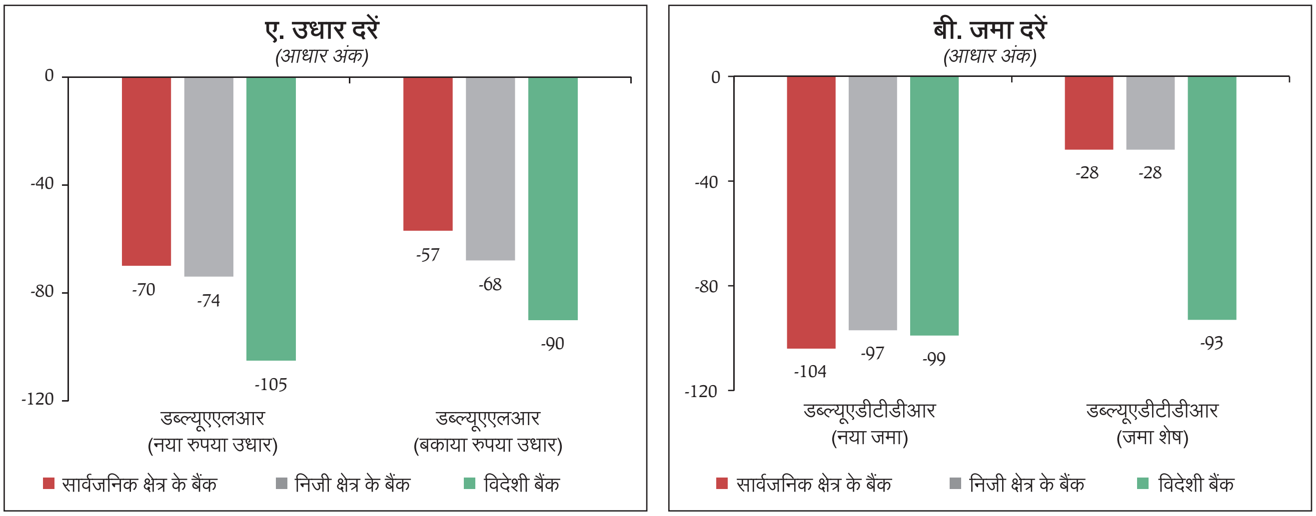

टिप्पणी: फरवरी से अक्तूबर 2025 के दौरान संचरण की गणना अक्तूबर 2025 की भारित औसत उधार और जमा दरों से जनवरी 2025 की भारित औसत उधार और जमा दरों को घटाकर की गई है।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.10: घरेलू इक्विटी बाजार में निरंतर पूंजी प्रवाह

(सूचकांक, दायाँ मान, ₹ हजार करोड़, बायाँ मान)

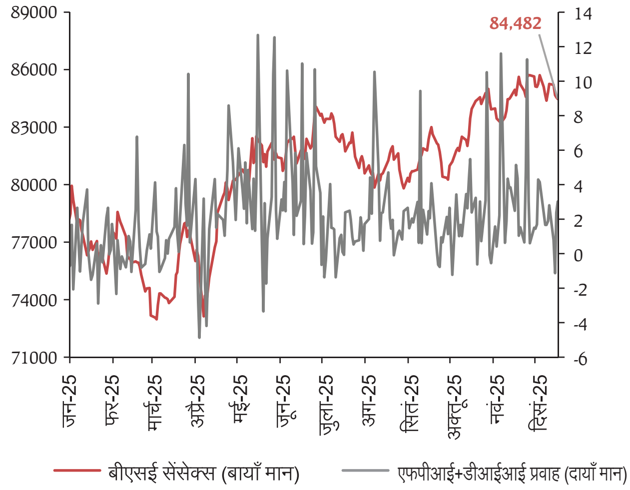

स्रोत: ब्लूमबर्ग; बीएसई; और एनएसई।

उच्च प्रत्यावर्तन और बहिर्गामी एफडीआई के कारण अक्तूबर में निवल एफडीआई नकारात्मक रहा। बहिर्गामी एफडीआई का प्रमुख गंतव्य सिंगापुर था। इसके बाद यूएस और संयुक्त अरब अमीरात का स्थान रहा, जिनका कुल बहिर्गामी एफडीआई में आधे से अधिक का योगदान रहा (चार्ट IV.11बी)। क्षेत्र-विशिष्ट विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग 90 प्रतिशत बहिर्गामी एफडीआई वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवाओं में था। इसके बाद थोक, खुदरा व्यापार और विनिर्माण का स्थान रहा।

2025-26 के दौरान अब तक (दिसंबर 2018 तक), इक्विटी क्षेत्र के कारण निवल एफपीआई में बहिर्वाह दर्ज किया गया।[38] पिछले दो महीनों में अंतर्वाह के बाद दिसंबर में एफपीआई प्रवाह नकारात्मक हो गया (चार्ट IV.12)। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और घरेलू बाजार के उच्च मूल्यांकन को लेकर निवेशकों की सतर्कता ने हाल के महीनों में भारत में निवल एफपीआई प्रवाह को कम रखा।

अप्रैल-अक्तूबर 2025 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के पंजीकरण में कमी आई, जो अपतटीय निधि जुटाने की गतिविधि में मंदी को दर्शाता है।[39] ईसीबी से निवल अंतर्वाह भी पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा (चार्ट IV.13)। ईसीबी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा[40] पूंजीगत व्यय के लिए जुटाया गया।

चार्ट IV:11 : स्थिर सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह

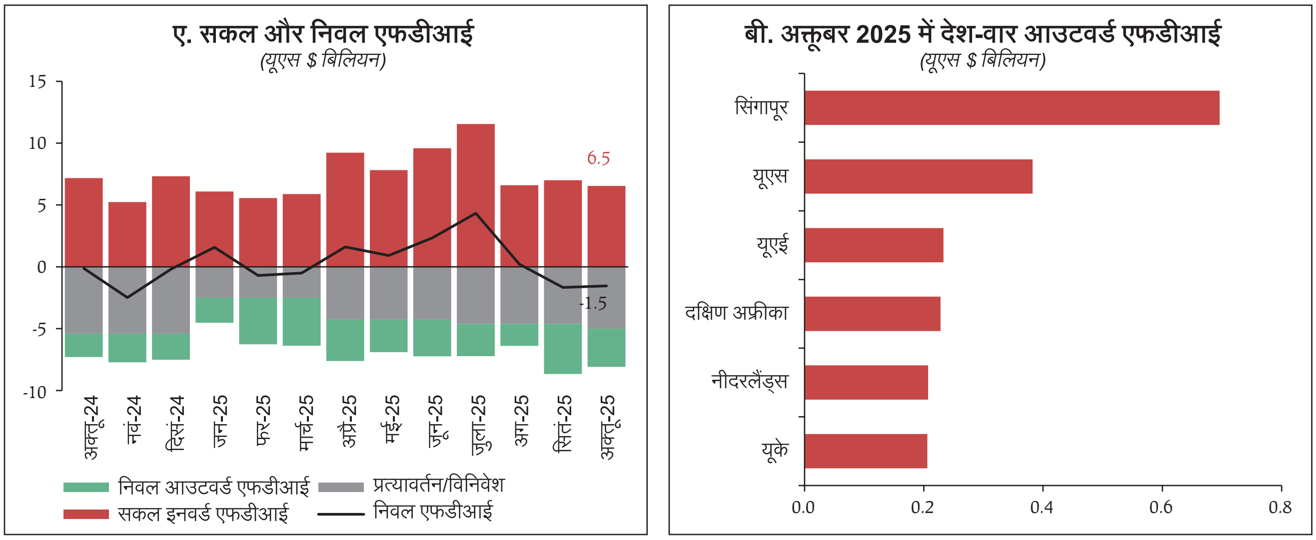

स्रोत: आरबीआई।

[38] 2025-26 के दौरान अब तक (18 दिसंबर तक) निवल एफपीआई बहिर्वाह लगभग 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

[39] अप्रैल-अक्तूबर 2025 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधारों का पंजीकरण घटकर 20.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में यह 30.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

[40] लगभग 45 प्रतिशत

चार्ट IV.12: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह में दिसंबर में कमी आई

(यूएस $ बिलियन)

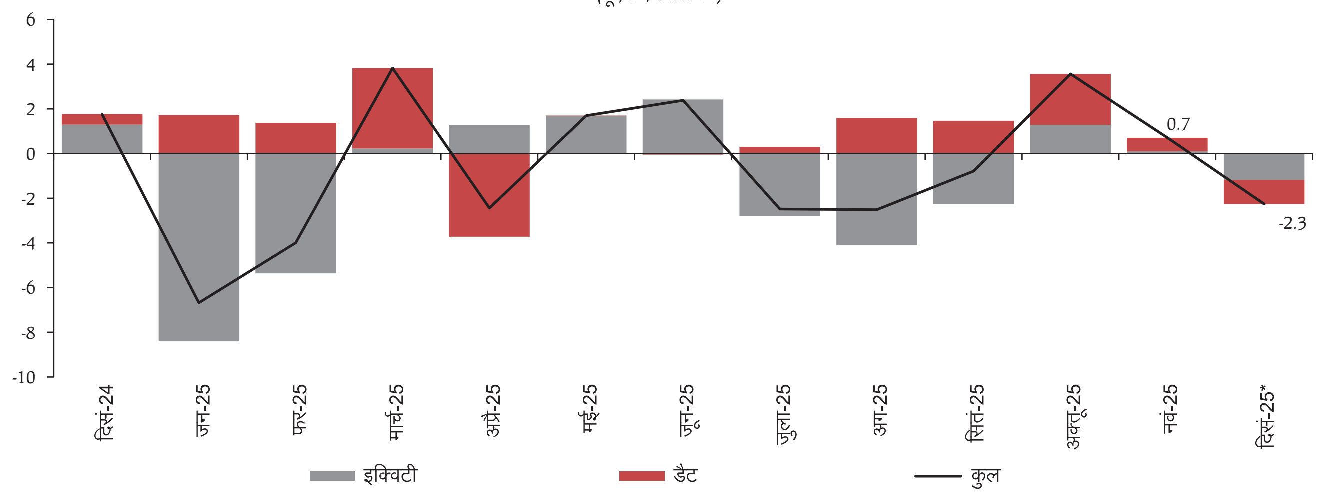

*: डेटा 18 दिसंबर तक से संबंधित है।
टिप्पणी: डेटा में हाइब्रिड लिखतों के अंतर्गत निवेश शामिल है।
स्रोत: नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)

भारत का चालू खाता घाटा 2025-26 की दूसरी तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम हुआ, जिसे पण्य व्यापार घाटे में कमी, सेवाओं के निर्यात में मजबूती और विप्रेषण से प्राप्त मजबूत आय से समर्थन प्राप्त हुआ (चार्ट IV.14)। हालांकि, निवल पूंजी अंतर्वाह चालू खाता वित्तपोषण आवश्यकताओं से कम रहा, जिससे विदेशी आरक्षित निधियों में कमी आई।[41] फिर भी, भारत की विदेशी आरक्षित निधियों पर्याप्त बनी हुई हैं, जो 11 महीने से अधिक के माल आयात और बकाया बाह्य ऋण के 92 प्रतिशत से अधिक के लिए पर्याप्त है (चार्ट IV.15)।[42]

चार्ट IV.13: बाहरी वाणिज्यिक उधार: पंजीकरण और प्रवाह

(यूएस$बिलियन)

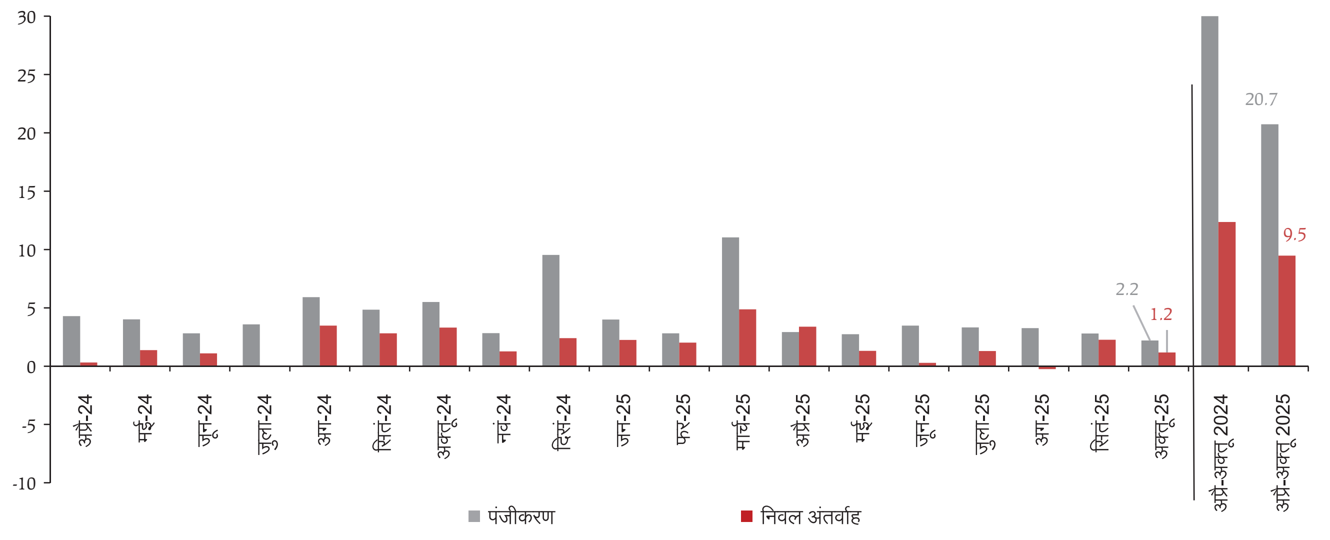

स्रोत: आरबीआई।

[41] 2025-26 की दूसरी तिमाही में विदेशी आरक्षित निधियों में 10.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई (बीओपी आधार पर), जबकि 2024-25 की दूसरी तिमाही में इसमें 18.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई थी।
[42] 12 दिसंबर 2025 तक, वस्तुओं और सेवाओं के लिए आयात कवर लगभग नौ महीने का था।

चार्ट IV.14:भारत के चालू खाते के घाटे में कमी आई

(यूएस $ बिलियन, बायाँ मान, माह, दायाँ मान)

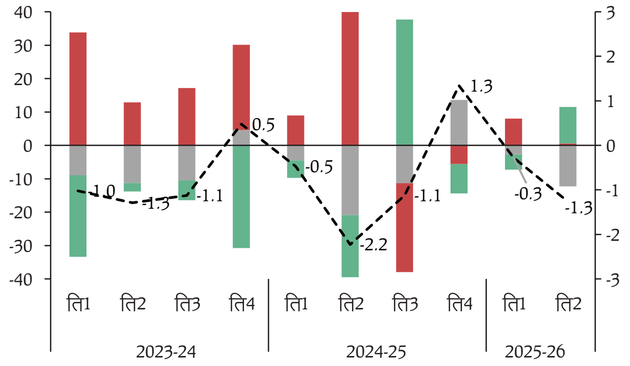

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.15 : भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ पर्याप्त रहीं

(यूएस $ बिलियन, बायाँ मान, माह, दायाँ मान)

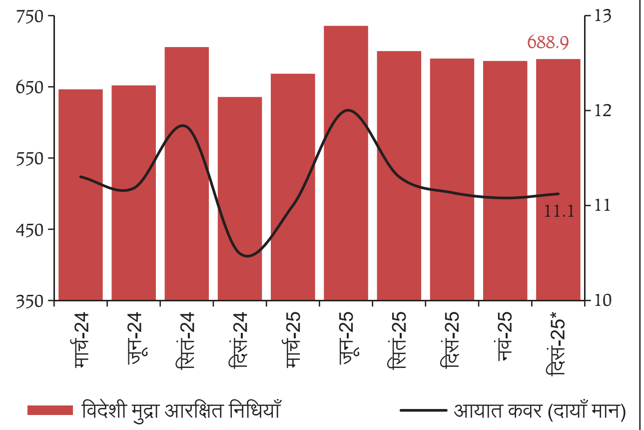

*12 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार

टिप्पणी: आयात कवर भुगतान संतुलन सांख्यिकी के अनुसार वार्षिकीकृत पण्य आयात पर आधारित है।

स्रोत: आरबीआई।

विदेशी मुद्रा बाजार

यूएस डॉलर के मजबूत होने, विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह में कमी और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता के दबाव के कारण नवंबर में भारतीय रुपया (आईएनआर) अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ (चार्ट IV.16)। परिवर्तनशीलता गुणांक द्वारा मापी गई आईएनआर की अस्थिरता नवंबर में पिछले महीने की तुलना में कम रही और अधिकांश प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम बनी रही। दिसंबर में अब तक (19 तारीख तक), आईएनआर नवंबर के अंत के स्तर से 0.8 प्रतिशत कमजोर हुआ है।

वास्तविक प्रभावी शर्तों में, भारतीय रुपया नवंबर में स्थिर रहा, क्योंकि सांकेतिक प्रभावी शर्तों में आईएनआर के मूल्यह्रास की भरपाई भारत में उसके प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की तुलना में उच्च कीमतों से हुई (चार्ट IV.17)।

चार्ट IV.16: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अन्य प्रमुख मुद्राओं का उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत, माह दर माह, बायाँ मान, प्रतिशत, दायाँ मान)

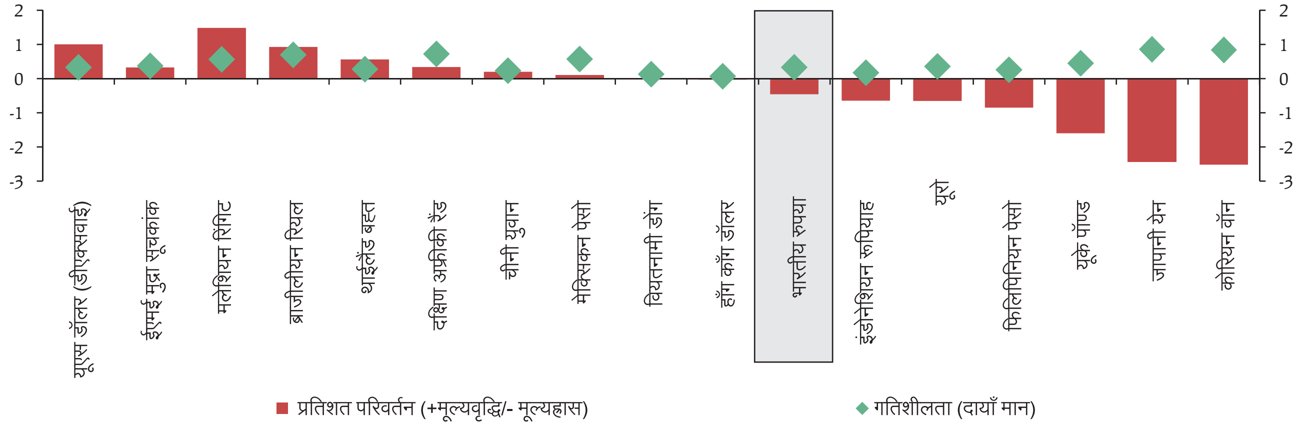

टिप्पणियाँ: 1. मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास (मा-द-मा) की गणना मासिक औसत विनिमय दर का उपयोग कर की जाती है।
2. यूएस डॉलर (डीएक्सवाई) प्रमुख मुद्राओं (यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना (स्विस फ्रैंक) के मुकाबले यूएस डॉलर की गतिविधि को मापता है।
3. नवंबर 2025 हेतु, प्रत्येक मुद्रा के लिए, गतिशीलता को दैनिक विनिमय दर डेटा का इस्तेमाल कर चर के गुणक(100* मानक विचलन/मध्यम) के तौर पर मापा जाता है।

स्रोत: एफबीआईएल; थॉमसन रॉयटर्स; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट IV.17: 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव

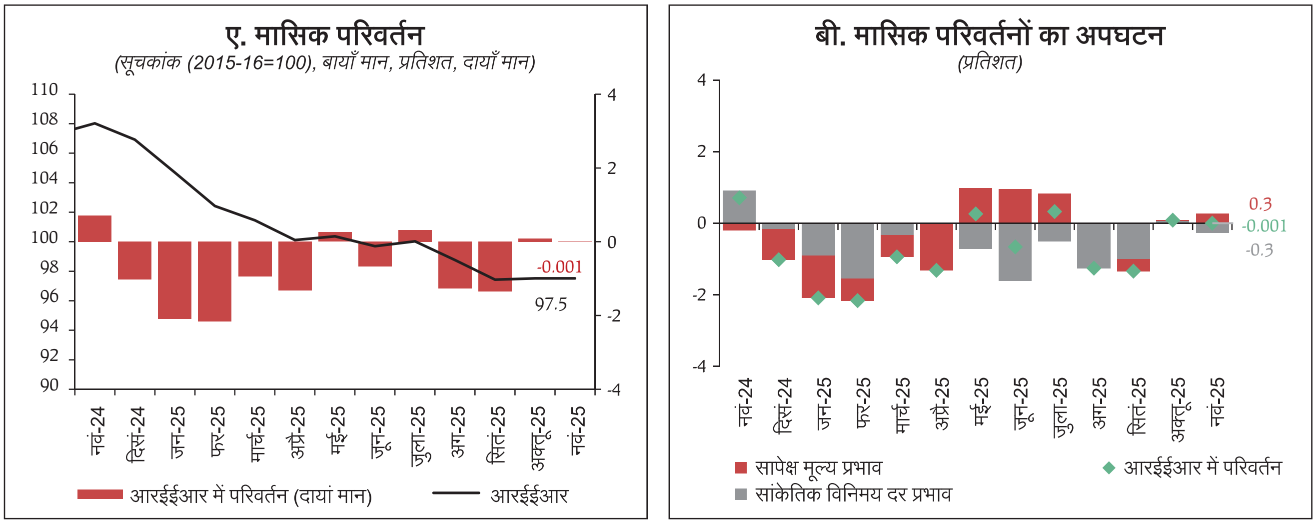

टिप्पणी: सकारात्मक परिवर्तन सांकेतिक और वास्तविक विनिमय दर में बढ़ोतरी और नकारात्मक परिवर्तन कमी की ओर संकेत करता है।
स्रोत: आरबीआई।

V. निष्कर्ष

वर्ष 2025 में वैश्विक व्यापार नीतियों में अभूतपूर्व बदलाव आया, जिसमें टैरिफ और व्यापार शर्तों पर द्विपक्षीय पुनर्विचार की दिशा में कदम उठाए गए। वैश्विक व्यापार प्रवाह और आपूर्ति शृंखलाओं पर इसके व्यापक प्रभाव अभी भी सामने आ रहे हैं। इससे वैश्विक अनिश्चितताएं और वैश्विक विकास की संभावनाओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दूसरी ओर, बिग टेक के प्रति आशावाद के चलते इक्विटी बाजार वर्ष के अधिकांश समय तक उत्साहपूर्ण रहे, हालांकि हाल ही में उच्च मूल्यांकन को लेकर चिंताओं ने इक्विटी बाजारों में कुछ जोखिम-विरोधी भावनाएं पैदा की हैं। हाल के महीनों में उभरते बाजारों में पोर्टफोलियो प्रवाह में भी मंदी देखी जा रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था बाह्य क्षेत्र की प्रतिकूलताओं से पूरी तरह अछूती नहीं रही। समन्वित राजकोषीय, मौद्रिक और विनियामक नीतियों ने वर्ष भर में मजबूती बनाए रखने में मदद की। मजबूत घरेलू मांग के कारण आर्थिक विकास मजबूत रहा।[43] अनुकूल मुद्रास्फीति परिदृश्य ने मौद्रिक नीति को विकास को समर्थन देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान की।[44] समष्टि आर्थिक मूलभूत सिद्धांतों और आर्थिक सुधारों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से दक्षता और उत्पादकता लाभ प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिससे तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश के बीच अर्थव्यवस्था को उच्च विकास पथ पर मजबूती से बनाए रखा जा सके।

[43] मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 5 दिसंबर 2025 के संकल्प में, 2025-26 के लिए विकास अनुमानों को 50 आधार अंक बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया गया, जो अक्तूबर की द्विमासिक समीक्षा के समय अनुमानित 6.8 प्रतिशत था।

[44] दिसंबर में हुई मौद्रिक नीति की बैठक में 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति के अनुमान को 60 आधार अंक घटाकर 2.0 प्रतिशत कर दिया गया, जो पहले 2.6 प्रतिशत था।

अनुबंध

सारणी ए1: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि

(व-द-व, प्रतिशत)

घटक	2024-25 में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	2024-25 में भारित योगदान (प्रतिशत अंक)	2024-25				2025-26	
			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2
I. कुल उपभोग व्यय निजी	**65.6**	**4.3**	**7.0**	**6.1**	**8.3**	**4.7**	**7.1**	**6.5**
खाजगी	56.5	4.0	8.3	6.4	8.1	6.0	7.0	7.9
सरकारी	9.1	0.2	-0.3	4.3	9.3	-1.8	7.4	-2.7
II. सकल पूंजी निर्माण	**36.8**	**2.5**	**6.2**	**7.7**	**4.9**	**7.8**	**7.3**	**5.1**
निश्चित निवेश	33.7	2.4	6.7	6.7	5.2	9.4	7.8	7.3
III. शुद्ध निर्यात	**-0.9**	**2.3**						
निर्यात	21.6	1.4	8.3	3.0	10.8	3.9	6.3	5.6
आयात	22.5	-0.9	-1.6	1.0	-2.1	-12.7	10.9	12.8
जीडीपी	**100.0**	**6.5**	**6.5**	**5.6**	**6.4**	**7.4**	**7.8**	**8.2**

टिप्पणी: अन्य शेष वस्तुओं के कारण घटकों का जोड़ कुल के बराबर न होने की संभावना है।
स्रोत: एनएसओ।

सारणी ए2: वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि

(व-द-व, प्रतिशत)

क्षेत्र	2024-25 में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	2024-25 में भारित योगदान (प्रतिशत अंक)	2024-25				2025-26	
			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2
I. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	**14.4**	**0.7**	**1.5**	**4.1**	**6.6**	**5.4**	**3.7**	**3.5**
II. उद्योग	**21.5**	**1.0**	**7.8**	**2.1**	**3.5**	**4.7**	**5.8**	**7.9**
खनन और उत्खनन	2.0	0.1	6.6	-0.4	1.3	2.5	-3.1	-0.04
विनिर्माण	17.2	0.8	7.6	2.2	3.6	4.8	7.7	9.1
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	2.4	0.1	10.2	3.0	5.1	5.4	0.5	4.4
III. सेवाएं	**64.1**	**4.8**	**7.2**	**7.4**	**7.5**	**7.9**	**9.0**	**9.0**
निर्माण	9.1	0.8	10.1	8.4	7.9	10.8	7.6	7.2
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	18.5	1.1	5.4	6.1	6.7	6.0	8.6	7.4
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं	23.8	1.7	6.6	7.2	7.1	7.8	9.5	10.2
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	12.7	1.1	9.0	8.9	8.9	8.7	9.8	9.7
आधार कीमतों पर जीवीए	**100.0**	**6.4**	**6.5**	**5.8**	**6.5**	**6.8**	**7.6**	**8.1**

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ की गणना।